टाइम्स ऑफ़ पीडिया

TIMES OF PEDIA

ٹائمس آف پیڈیا

अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इंसाफ़ की डगर पर

NEW DELHI Page 12 Price Rs. 3.00 | www.timesofpedia.com | WEEKLY HINDI, ENGLISH, URDU

WED 25 FEB - TUE 03 MARCH 2026 | VOL. 14. ISSUE 09 | RNI No. DELMUL/2012/47011

अमेरिका - इज़राइल हमलों में ईरान के 131 शहर प्रभावित, 555 मौतों का दावा

तेहरान/वॉशिंगटन। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए हवाई हमलों में अब तक 555 लोगों की मौत हो चुकी है तथा 131 शहर प्रभावित हुए हैं। ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के हवाले से अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने बताया कि जारी एयरस्ट्राइक अभियान में बड़ी संख्या में नागरिक और सुरक्षा कर्मी हताहत हुए हैं। हालांकि इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

रेड क्रिसेंट ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। देशभर में एक लाख से अधिक राहतकर्मी अलर्ट पर हैं, जबकि लाखों स्वयंसेवकों का नेटवर्क मानवीय सहायता और मनोसामाजिक सहयोग प्रदान करने के लिए तैयार रखा गया है। ईरान ने कहा कि हमलों से कई शहरों में बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है।

इस बीच क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है। रिपोर्टों के अनुसार, ईरान और उसके समर्थित गुटों ने इजराइल तथा कुछ अन्य देशों की ओर मिसाइलें दागीं। जवाब में इजराइल और अमेरिका ने ईरानी ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। खाड़ी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी सुरक्षा सतर्कता बढ़ा दी गई है।

कुवैत सिटी में स्थित अमेरिकी दूतावास परिसर के पास धुआं उठने की खबरें सामने आई, हालांकि किसी बड़े नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इराक में एक ईरान समर्थक मिलिशिया ने बगदाद एयरपोर्ट के निकट अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली है।

तनाव के बीच ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों ने अमेरिका से किसी भी प्रकार की वार्ता से इनकार किया है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने सभी पक्षों से संयम बरतने और तत्काल तनाव कम करने की अपील की है, क्योंकि बढ़ता संघर्ष पूरे पश्चिम एशिया क्षेत्र की स्थिरता पर व्यापक असर डाल सकता है।

पीएम मोदी - कार्नी वार्ता में यूरेनियम आपूर्ति सहित कई अहम समझौते

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में यूरेनियम आपूर्ति सहित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति बनी। दोनों देशों ने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार सहयोग को नई गति देने पर जोर दिया। वार्ता के बाद साझा बयान में कहा गया कि भारत-कनाडा संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा।

बैठक के दौरान स्वच्छ ऊर्जा और परमाणु सहयोग विशेष चर्चा के केंद्र में रहे। कनाडा ने भारत को दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई, जिससे भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। दोनों पक्षों ने ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई।

इसके अतिरिक्त, रक्षा निर्माण, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। व्यापार और निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए संयुक्त कार्यबल के गठन पर भी सहमति बनी। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और कनाडा साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़े देश हैं और दोनों के बीच आर्थिक व सामरिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री ने भी भारत को एक प्रमुख वैश्विक साझेदार बताते हुए आपसी विश्वास और सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की बात कही।

विशेषज्ञों का मानना है कि इन समझौतों से दोनों देशों के संबंधों में नई ऊर्जा आएगी और वैश्विक मंच पर सहयोग के नए आयाम खुलेंगे।

इसके साथ ही दोनों नेताओं ने लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने और प्रवासी समुदाय की भूमिका को और सशक्त बनाने पर भी बल दिया। शिक्षा, कौशल विकास और अनुसंधान के क्षेत्र में संयुक्त कार्यक्रम शुरू करने पर सहमति बनी, ताकि दोनों देशों के युवा और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ मिल सके। छात्र विनिमय कार्यक्रमों को सरल बनाने तथा पेशेवरों की आवाजाही को सुगम करने के उपायों पर भी चर्चा हुई। वार्ता में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के मुद्दे भी उठाए गए। दोनों पक्षों ने भरोसेमंद और विविधीकृत सप्लाई चेन विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच आर्थिक स्थिरता बनी रहे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और फिनटेक सहयोग को भी प्राथमिकता देने पर सहमति व्यक्त की गई।

मुख्य समाचार

तनाव के माहौल में बड़ी राहत, 600 भारतीयों की घर वापसी

नई दिल्ली। ईरान पर अमेरिका और इजरायल की ओर से किए गए हमलों के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति बनी हुई है। क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर देश में भी चिंता का माहौल है। इस बीच सोमवार रात राहत भरी खबर सामने आई, जब दुबई और अबू धाबी से दो विशेष उड़ानों के जरिए 600 से अधिक भारतीयों और कुछ अन्य देशों के नागरिकों को सुरक्षित दिल्ली लाया गया।

जानकारी के अनुसार, तीन दिनों के अंतराल के बाद मिडिल ईस्ट से पहली उड़ान एतिहाद एयरवेज की सोमवार रात दिल्ली हवाईअड्डे पर उतरी।

AI से बने फर्ज़ी फ़ैसलों पर सुप्रीम कोर्ट सख़्त

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा कथित रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से तैयार गैर-मौजूद और फर्जी न्यायिक निर्णयों पर भरोसा किए जाने को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे नकली और अस्तित्वहीन फैसलों के आधार पर पारित आदेश को केवल विधिक त्रुटि नहीं माना जा सकता, बल्कि यह कदाचार की श्रेणी में आ सकता है और इसके विधिक परिणाम होंगे।

जस्टिस पामिडिघंतम श्री नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के एक सिविल पुनरीक्षण आदेश से संबंधित विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा AI से तैयार गैर-मौजूद या कृत्रिम निर्णयों का उपयोग न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सीधा प्रभाव डालता है।

Editor/Owner/Printer/Publisher: Ali Aadil Khan, K-2-A-001, Abul Fazal Enclave-l, Jamia Nagar, Okhla, ND - 25. **Printed at:** Shobi Offset Press, 2818, Gali Gadhiaiya, Kuchachalan, Daryaganj, ND. -2

ईरानी सुप्रीमो अयातुल्लाह अली ख़ामनेई आज भी ज़िंदा?

Ali Aadil Khan
Editor

वो हो गए शहीद ये एज़ाज तो मिला
अहल-ए-जुनूँ को नुक्ता-ए-आगाज तो मिला
कोई भी इस जहां में हमेशा नहीं रहा
आखिर तो नूह को भी, जामे कजा मिला

आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद भारत के साथ साथ दुनिया भर में सेह्यूनियत और साम्राजयवाद के ख़िलाफ़ प्रदर्शन हुए और ताज़यती जुलूस निकाले गए , अली खामनेई की शहादत पर सोग में डूबे ईरान के अलावा दुनिया भर में भारी ग़मो ग़ुस्सा पाया जा रहा है .

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खामेनेई की हत्या को (निंदनीय हत्या) बताते हुए कहा की अली खामनेई की हत्या नैतिकता और अंतरराष्ट्रीय कानून की ख़िलाफ़ वर्ज़ी है । साथ ही चीनी विदेश मंत्रालय ने हमले की कड़ी निंदा की है और इसे अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन बताया है। चीन ने खामेनेई की मौत को ईरान की संप्रभुता (sovereignty) और सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन करार दिया है।

रूस और चीन सिर्फ हमलों की निंदा ही कर सकते हैं असल में तहज़ीबों के ज़िंदा रखने की लड़ाई मुसलमानों को ही लड़नी होगी. और साथ ही दुनिया के हर मज़लूम की लड़ाई को अपना समझना होगा और हक़ को ज़िंदा करने के लिए जद्दो जेहद करना होगा . कर्बला में हुसैन की रंजिश यज़ीद से नहीं थी बल्कि हक़ को ज़िंदा रखने की वो जंग थी.

ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत पूरी दुनिया के हक़परस्तों के लिए इंतहाई ग़म और जज़्बाती लम्हात के साथ मुस्लिम वर्ल्ड के लिए लम्हा ए फिक्रिया है । इस्लामिक और ऐतिहासिक संदर्भों के अनुसार जिन लोगों ने सबसे ज्यादा पैगंबरों (नबियों/रसूलों) को सताया और शहीद किया वह बनी इसराइल यानी (Yahudi) कौम थी।

आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी यहूदियों ने फांसी पर चढ़ाया था मगर अल्लाह ने यहूद की इस ख्वाहिश को पूरा न होने दिया और अपने रसूल ईसा इब्न ए मरयम को आसमान में ज़िंदा उठा लिया. और यही मग़ज़ूब क़ौम है यानी यहूद ...और यही क़यामत की होलनाकी को देखेंगे..

मरहूम अली खामनेई ने 38 बरसों तक अपनी क़ौम का नेतृत्व किया और Regional Politics में एक मज़बूत, निडर, तरक़्क़ी पसंद, शरीअत के पाबन्द और प्रभावशाली

मर्ग-ए-यजीद है
इस्लाम जिंदा होता है हर
कर्बला के बाद

आज पूरी दुनिया में अम्न और हक़ पसंदों को मुत्तहिद हो जाना चाहिए, साथ ही शांति, धैर्य और स्थिरता की भी दुआएं करने की इंतहाई ज़रुरत है, ताकि ज़मीन पर अमन और इंसानियत क़ायम रह सके, और शेतनत का ख़ात्मा हो सके । आज जिसको फादर ऑफ़ लैंड कहा जा रहा है वो दरअसल नाजाइज़ औलाद की पनाहगाह है, फ़ित्नों फसाद की धरती है , दुनिया

Revolution के सक्रिय नेता रहे और इसके 10 साल बाद यानी Ruhollah Khomeini के इंतिक़ाल के बाद जम्हूरिया ए इस्लामी ईरान में मरकज़ी रहनुमा की हैसियत से बाक़ायदा अपनी खिदमात का आग़ाज़ किया।

पूरी क़ौम ने उनको अपना सुप्रीम लीडर माना. इसके बाद से लगातार 38 बरस तक ईरान की सियासी बागडोर संभाली। उनके दौर इक़्तेदार में ईरान ने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई बड़े उतार-चढ़ाव देखे. जिनमें पश्चिमी दुनिया यानी WESTERN WORLD और अमेरिका के सामने बेबाकी और बहादुरी के साथ चुनौती बनकर खड़े रहे . अयातुल्लाह अली खामनेई का जस्दे खाकी बेशक दुनिया में नहीं रहा लेकिन ईरान के सुप्रीमो अभी क़ौम और चाहने वालों के दिलों में अज्ज भी ज़िंदा हैं और हमेशा रहेंगे? ज़ुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने और ज़ालिम के पंजाये इस्तबदाद को मरोड़ने वालों में अली खामनेई का नाम लिखा जाएगा, अब रहा नीयत और अक़ीदे का सवाल

क़ायद की भूमिका निभाई।

टाइम्स ऑफ़ पीडिया ग्रुप इस कठिन समय में ईरान की जनता और दुनिया भर में उनके चाहने वालों के प्रति गहरी संवेदना और खिराजे अक़ीदत पेश करता है। दुआ है कि अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, उनसे मोहब्बत करने वालों को सब्र-ए-जमील अता फरमाए, और क़ौम को जल्द उनका मुताबादिल आता करे ...आमीन ।

कत्ल-ए-हुसैन अस्ल में

के सारे बड़े राक्षसी काम इसी सोच और इसी धरती से किये जा रहे हैं तारीख़ इसकी शाहिद है. तरक़्क़ी और विकास के नाम पर इंसानियत और इंसानों के अधिकारों को छीना जा रहा है. आयतुल्लाह खामनेई 19 जुलाई 1939 को ईरान के शहर Mashhad में पैदा हुए । कम उम्र में ही उन्होंने मज़हबी तालीम हासिल की और दुनिया के इस्लामिक scholars में उनका शुमार हुआ। 1979 की Iran में Islamic

देशों के साथ परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव, आर्थिक प्रतिबंध, तथा क्षेत्रीय संघर्ष जैसे अहम मुद्दे शामिल रहे। उनके दौर में 2015 का परमाणु समझौता, जिसे दुनिया Joint Comprehensive Plan of Action के नाम से जानती है, एक ऐतिहासिक पड़ाव साबित हुआ। साथ ही, मध्य पूर्व की बदलती सियासत और सुरक्षा चुनौतियों के बीच उन्होंने देश की नीतियों को दिशा दी। पूरी मशरिकी

तो वो आख़िरत में तय होगा अभी कोई नहीं जानता.

दुनिया भी अपने खात्मे की तरफ बढ़ रही है और हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है लेकिन ईरान के बुज़ुर्ग क़ायद मरहूम अयातुल्लाह अली खामनेई सुन्नी दुनिया को जाते जाते एक पैग़ाम दे गए कि....

मौत की आग में तप तप के
निखरती है हयात!
डूब कर जंग के दरिया में जरा,
तुम भी देखो !!!

पश्चिम एशिया में संघर्ष तेज़ हुआ; इज़रायल ने तेहरान और बेरूत के सैन्य ठिकानों पर एक साथ हमले किए

ईरान। ईरान और संयुक्त इस्राएल-अमरीकी बलों द्वारा नए मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद पश्चिम एशिया में संघर्ष तेज हो गया है। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार इस्राएल वर्तमान में तेहरान और बेरूत में सैन्य ठिकानों पर एक साथ लक्षित हमले कर रहा है।

इस्राएल रक्षा बलों ने कहा है कि उसके सैनिक दक्षिणी लेबनान में अग्रिम रक्षा रणनीति के अंतर्गत सीमा क्षेत्र के निकट कई स्थानों पर तैनात हैं। इस्राएली रक्षा बलों के अनुसार इस्राएल हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचों पर लक्षित हमले कर रहा है। इस्राएल ने आरोप लगाया कि हिजबुल्लाह ने ईरानी शासन की ओर से इस्राएल पर हमला करने का विकल्प चुना।

इस्राएली रक्षा बलों ने कहा कि इस्राएली हमलों में बेरूत में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के कमांडर अबू हमजा रामी मारे गए हैं। अबू हमजा रामी की हत्या से इस्राएल के खिलाफ अभियान चलाने की फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद की क्षमता कमजोर हो गई है। एक अन्य हमले में, इस्राएली बलों ने बेरूत में हिजबुल्लाह के खुफिया मुख्यालय के प्रमुख हुसैन मकलद को भी मार गिराया।

इसके अलावा, अमरीका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि अमरीकी सेना ने लगातार अभियानों के दौरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमान और नियंत्रण केंद्रों, ईरानी वायु रक्षा क्षमताओं, मिसाइल और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों और सैन्य हवाई अड्डों को नष्ट कर दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सेंटकॉम ने कहा कि अमरीका ईरानी शासन से उत्पन्न होने वाले खतरों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई जारी रखेगा। इस बीच, अब तक छह अमरीकी सैनिक कार्रवाई में शहीद हो चुके हैं। दूसरी ओर, ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया कि बहरीन में अमरीका की वायु सेना के एक अड्डे पर स्थित कमांड भवन नष्ट हो गया है।

बहरीन के अमेरिकी राजदूत अब्दुल्ला बिन राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा ने कहा कि बहरीन की वायु रक्षा प्रणाली ने बहरीन को निशाना बनाकर दागी गई 70 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों और 59 ड्रोनों को नाकाम कर दिया।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बहरीन में नागरिक स्थलों पर तेहरान द्वारा हमला किया गया था।

सऊदी अरब के रियाद स्थित अमरीकी दूतावास पर भी तेहरान से दागे गए दो ड्रोनों ने हमला किया। ड्रोन हमले में मामूली नुकसान हुआ। इस हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका जवाबी कार्रवाई करेगा।

इस बीच इस्लामिक गणराज्य में बढ़ते संघर्ष के बीच, ईरान के गेराश क्षेत्र में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया। अभी किसी बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है।

NOTICE:
Times of Pedia does not guarantee, directly or indirectly, the quality or efficacy of any product or services described in the advertisements or other material which is commercial in nature in this Newspaper. Furthermore, Times of Pedia assumes no responsibility for the consequences attributable to inaccuracies or errors in the printing of any published material from the news agencies or articles contributed by readers. It is not necessary to agree with the views published in this Newspaper. All disputes to be settled in Delhi Courts only.

अमरीका ने पश्चिम एशिया में जारी संकट के मददे नज़र 24 घंटे चलने वाला अंतर-एजेंसी कार्य बल सक्रिय किया

अमरीका ने पश्चिम एशिया में जारी संकट के मद्देनजर वाणिज्यिक मामलों, नागरिक सुरक्षा और राजनयिक सुरक्षा विशेषज्ञों का 24 घंटे सातों दिन चलने वाला अंतर-एजेंसी कार्य बल सक्रिय कर दिया है। यह कार्य बल वाशिंगटन स्थित एक समर्पित संचालन केंद्र से कार्य कर रहा है, जहां एक संकट संचार टीम 110 से अधिक अंतर-एजेंसी प्रतिभागियों और प्रभावित दूतावासों के साथ प्रतिदिन समन्वय कॉल कर रही है।

इस बीच, अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने एक वीडियो संदेश में अमरीकियों से मध्य पूर्व के प्रमुख हिस्सों को तुरंत छोड़ने का आग्रह किया है और क्षेत्र में बढ़ते तनाव के कारण गंभीर सुरक्षा खतरों की चेतावनी दी है।

इसी घटनाक्रम में, अमरीकी वाणिज्यिक मामलों की सहायक सचिव मोरा नामदार ने कहा कि विदेश विभाग गंभीर सुरक्षा खतरों के कारण अमरीकियों से उपलब्ध वाणिज्यिक परिवहन का उपयोग करके कई देशों से तुरंत निकलने का आग्रह किया है। इन देशों में बहरीन, मिस्र, ईरान, इराक, इस्राएल, पश्चिमी तट और गजा, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, संयुक्त अरब अमीरात और यमन शामिल हैं।

आईएनएसवी कौंडिन्या ओमान के मस्कट की अपनी पहली विदेशी यात्रा के बाद स्वदेश लौटा

भारतीय नौसेना का पोत-आईएनएसवी कौंडिन्या ओमान के मस्कट की अपनी पहली विदेशी यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न करने के बाद स्वदेश लौटा। परेड और पारंपरिक सलामी के साथ पोत का स्वागत किया गया, जिससे बंदरगाह में एक भव्य और भावपूर्ण वातावरण बन गया। यह आयोजन भारत की समुद्री विरासत पर गर्व और चालक दल की उपलब्धि के प्रति प्रशंसा का प्रतीक था। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और पश्चिमी नौसेना कमान के कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में पोत का ध्वजारोहण किया।

मुंबई में ओमान सल्तनत के महावाणिज्यदूत श्री महबूब ईसा अलरैसी, नागरिक समाज के प्रतिष्ठित सदस्य, समुद्री समुदाय के सदस्य, इतिहासकार और नौकायन प्रेमी इस अवसर पर उपस्थित थे।

होलिका दहन और स्त्री गरिमा: परंपराओं के पुनर्पाठ की आवश्यकता

कपिल बर्मन

'नारी पूज्यते यत्र, रमन्ते तत्र देवता:' यह सूत्र हमारे ऋषियों ने दिया। पर क्या यह मात्र एक आदर्श वाक्य बनकर रह गया है? क्या हमने सदियों से इस सत्य को केवल दोहराया है, जिया नहीं? आज प्रश्न यह नहीं कि हम नारी को क्या कहते हैं, प्रश्न यह है कि हम उसके साथ क्या करते हैं।

होलिका : पुनर्पाठ की माँग करती एक कथा:

होलिका दहन की कथा को जितनी बार सुना, उतनी बार एक प्रश्न मन में कौंधता रहा – यदि होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती, तो वह जल कैसे गई? यदि वह बुआ थी, तो क्या कभी किसी बुआ ने अपने भतीजे को जलाने की सोची? बुआ तो अपने भतीजे से अपने पुत्र से भी अधिक स्नेह करती है – यह हमारे समाज का सनातन सत्य है।

तो फिर यह कथा क्या कहती है? क्या यह हमें कोई और सत्य बताने का प्रयास कर रही है?

वैकल्पिक इतिहास : होलिका की बुद्धिमत्ता का अपमान :

विचार करें –होलिका एक तार्किक, बुद्धिमान और स्वतंत्र चेतना वाली स्त्री थी। उसने उस बाहरी संस्कृति का प्रतिरोध किया जो शोषण और अन्याय पर आधारित थी। जो संस्कृति समानता का दिखावा करते हुए वर्चस्व स्थापित करना चाहती थी। होलिका ने उस सभ्यता के झूठे आदर्शों को उजागर किया।

परिणाम? उसे जला दिया गया प्रतीकात्मक रूप से नहीं, शाब्दिक रूप से। और आज हम प्रतिवर्ष उसी स्त्री के दहन का उत्सव मनाते हैं, उसे 'राक्षसी' कहते हैं, उसके प्रतिरोध को 'बुराई' का नाम देते हैं।

स्त्री–दहन की परंपरा : सती से होलिका तक :

हमारे समाज ने सदियों से स्त्री को जलाने की परंपरा निभाई है:

सती प्रथा : पति की मृत्यु पर पत्नी को चिता में जलना अनिवार्य

देवदासी प्रथा : मंदिरों में स्त्रियों को देवता के नाम पर समर्पित कर उनका शोषण

दहेज प्रथा : पर्याप्त दहेज न मिलने पर विवाहिता को जलाना

होलिका दहन :एक स्त्री के प्रतिरोध को प्रतिवर्ष जलाने का उत्सव

यह कोई संयोग नहीं है। यह एक पैटर्न है –स्त्री की स्वतंत्र चेतना को, उसके तर्क को, उसके प्रतिरोध को जलाने का पैटर्न।

होलिका की आवाज़ : आज की आवश्यकता :

होलिका मरती नहीं, वह प्रतिवर्ष जलती है – हमारी आस्था की आग में। वह चिल्लाती है, पर हम सुनना नहीं चाहते। वह प्रश्न करती है, पर हम उसे 'राक्षसी' कहकर खारिज कर देते हैं।

आज आवश्यकता है – होलिका की आवाज़ सुनने की। उसके प्रश्नों का सामना करने की। उसके तर्क को समझने की।

यदि होलिका राक्षसी थी, तो उसके पिता हिरण्यकश्यप को राक्षस क्यों नहीं कहा जाता?

यदि वह बुरी थी, तो उसे वरदान क्यों मिला?

यदि वह अग्नि में नहीं जल सकती थी, तो वह जल कैसे गई? ये प्रश्न हमारी कथाओं के पुनर्पाठ की माँग करते हैं।

नारी गरिमा : पुनर्विचार का आह्वान :

हम सदियों से रूढ़ियाँ ढो रहे हैं। परंपरा के नाम पर अन्याय स्वीकार कर रहे हैं। आस्था की आड़ में अपमान सही ठहरा रहे हैं।

समय है – हम होलिका दहन का नहीं, होलिका के अपमान का दहन करें। उस सोच को जलाएँ जो स्त्री को जलाने का उत्सव मनाती है

उस परंपरा को जलाएँ जो स्त्री के प्रतिरोध को 'बुराई' कहती है

उस व्यवस्था को जलाएँ जो स्त्री के तर्क को दबा देती है

निष्कर्ष : नारी, तू जलने के लिए नहीं, जलाने के लिए है :

होलिका की असली कहानी यह है –एक स्त्री ने प्रश्न किया। एक स्त्री ने प्रतिरोध किया। एक स्त्री ने अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई। और उसे जला दिया गया।

आज, उसी स्त्री के दहन के उत्सव में, हमें निर्णय लेना है – क्या हम उसे फिर जलाएँगे, या उसकी आवाज़ बनेंगे? 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता:' –यह सूत्र तभी सार्थक होगा, जब हम नारी को जलाने की परंपरा को जलाकर, उसे जीने का अधिकार देंगे। होलिका की जलती चिता से उठी चिंगारी आज हमारे विवेक को जला रही है। क्या हम बुझाएँगे या स्वयं जलेंगे?

बढ़ते वैश्विक तनाव के बीच विश्व युद्ध की आशंका

Aditya Chopra

इजराइल और अमेरिका द्वारा मिल कर ईरान के विरुद्ध छेड़े गये युद्ध से अब पूरी दुनिया में भारी अफरा-तफरी की आशंका पैदा होती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि विश्व के विभिन्न देशों की सबसे बड़ी पंचायत 'संयुक्त राष्ट्रसंघ' एक मूकदर्शक बन चुकी है। जिस प्रकार इजराइली-अमेरिकी हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई की हत्या की गई है उसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह ईरान के लोगों द्वारा अपने लिए चुनी गई शासन व्यवस्था पर विदेशी आक्रमण है। श्री खामेनेई की हत्या के बाद ईरान के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और वे सड़कों पर निकल कर अमेरिका से बदला लेने की मांग कर रहे हैं। भारत शुरू से ही यह मानता रहा है कि किसी भी देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था काबिज हो, इसका फैसला सिर्फ उस देश की जनता को ही करने का अधिकार होता है। अत: ईरान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जिस तरह सत्ता परिवर्तन को इस युद्ध का ध्येय बता रहे हैं उसका कोई औचित्य नहीं है लेकिन ईरान में अमेरिकी कार्रवाई के बाद पश्चिम एशिया के मुस्लिम देशों से प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है वह इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता और सौहार्दता के माहौल के लिए खतरा पैदा करती है। श्री खामेनेई पूरी दुनिया के शिया मुस्लिम सम्प्रदाय के लोगों के नेता भी माने जाते थे अत: उनकी हत्या के बाद कई मुस्लिम देशों में लोग सड़कों पर उतर कर विरोध-प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इसका प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप के देशों तक पर पड़ा है, मगर असली सवाल यह है कि क्या यह युद्ध जल्दी ही समाप्त हो जायेगा अथवा लम्बे समय तक खिंचेगा? इस सन्दर्भ में हमें इस तथ्य पर गौर करना होगा कि ईरान की सैन्य क्षमता कितनी है और उसके समर्थन में कौन-कौन सी विश्व शक्तियां खड़ी हुई हैं? इस मामले में रूस व चीन का नाम लिया जा सकता है क्योंकि ये दोनों देश ही आर्थिक व सैनिक रूप से ईरान के सहयोगी रहे हैं परन्तु इसके साथ यह भी देखना होगा कि इन दोनों देशों के पश्चिम एशिया में अपने-अपने हित किस प्रकार सधते हैं। इस क्षेत्र के अधिकतम मुस्लिम देशों के शासक अमेरिका परस्त माने जाते हैं जिसकी वजह से इस क्षेत्र के पूरे समुद्री इलाके में अमेरिकी जंगी जहाजी बेड़ों का पूरा काफिला तैनात रहता है तथा जमीन पर इनमें से अधिसंख्य में अमेरिकी सैनिक अड्डे हैं। अत: ईरान ने पलटवार करते हुए सबसे पहले इन्हीं सैनिक अड्डों को अपना निशाना बनाया है। उसने अभी तक बहरीन, कतर , संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब व जोर्डन स्थित अमेरिकी सैनिक अड्डों पर हमले करके उन्हें तहस-नहस करने का प्रयास इसीलिए किया है जिससे उसके इजराइल पर किये जाने वाले हमलों में किसी प्रकार का अवरोध पैदा न हो। इससे लगता है कि ईरान को अमेरिका की मंशा पर पहले से ही अन्देशा था और वह जानता था कि अमेरिका उसे बातचीत में उलझा कर अचानक हमला बोल सकता है। उसकी यह रणनीति पिछले वर्ष इजराइल से चली क्ख रोजा जंग के बिल्कुल विपरीत है।

पिछले वर्ष ईरान ने इजराइल पर जो मिजाइल हमले किये थे उन्हें बीच में ही इन अड्डों से प्रतिरोधी अस्त्र चला कर बड़ी हद तक नाकामयाब कर दिया जाता था। ईरान की सबसे बड़ी सैन्य ताकत उसका अत्याधुनिक मिजाइल जखीरा है जो उसे रूस व चीन के सहयोग से प्राप्त हुआ है। उसके पास ड्रोन आक्रमण की क्षमता भी अद्भुत है मगर इनके भरोसे वह अमेरिका जैसी महाशक्ति से पार नहीं पा सकता है, अत: संभावना यह व्यक्त की जा रही है कि उसकी मदद के लिए कहीं रूस व चीन न कूद पड़ें। यदि ऐसा होता है तो इस युद्ध के विश्व युद्ध में बदलने की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पिछले कई वर्षों से उसके खिलाफ मुहीम छेड़े हुए हैं और वह नहीं चाहता कि ईरान किसी भी सूरत में परमाणु बम बनाये। इसके चलते पिछले लगभग डेढ़ दशक से अमेरिका ने ईरान पर विविध आर्थिक प्रतिबन्ध भी लगाये हुए हैं। दूसरी तरफ ईरान का कहना रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शान्तिपूर्ण विकास के लिए ही है जिसे करने का उसे पूरा हक है। इसी मुद्दे पर अमेरिका व ईरान के बीच पिछले दिनों से वार्तालाप भी चल रही थी जिसकी मध्यस्थता ओमान कर रहा था। इस सन्दर्भ में ईरान इस बात के लिए भी राजी हुआ कि उसके परमाणु कार्यक्रम का निरीक्षण अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी भी करे मगर उसे यूरेनियम परिशोधन करने से नहीं रोका जा सकता। यह भी पूरी दुनिया जानती है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम रूस के सहयोग से ही कर रहा था लेकिन अमेरिका ने ओमान की मध्यस्थता में चल रही शान्ति वार्ता के दौरान ही इजराइल के साथ मिलकर हमला कर दिया और इसके सर्वोच्च नेता खामेनेई के साथ ही इसके रक्षामन्त्री व फौजी कमांडर को भी निशाना बना डाला।

RSS Chief's Call for intensifying Ghar Wapasi

Prof. Ram Puniyani

Choosing one's religion is a social and legal right of citizens' as per Indian Constitution. Still the organizations who do their politics under the cover of religion do not accept this. Dr. Mohan Bhagwat, the Sarsanghachalak of RSS keeps stating on one hand that all people living in this country are Hindus, on the other hand he says that Hindu population is declining as many of them are being converted to Islam and Christianity. He further went on to say that Hindu couples should produce three children as declining population of Hindus in the country is worrisome.

It is contradictory that on one hand you call every body Hindu and on the other you call for Ghar Wapasi into Hinduism. Many of them emphasise that the DNA structure of all communities in India is similar. As far as population genetics is concerned it is no indicator of one's religion and the global migrations took place and determine the similarity of DNA amongst different religions is a fact. Just because DNA studies reveal many similarities, it is no argument for leaving one's religion of inheritance or choice to leave and merge into the majority religious community.

The argument that Islam in India spread on the strength of sword of kings holds no water as the first Muslim population of India developed in Malabar Coast, Kerala. This was not due to the sword of the king, as there was no Muslim king in Kerala till 15th Century when Tipu Sultan annexed it. The first mosque in India came up in 7th Century itself, Cheramaan Juma Mosques. Later while few conversions to Islam might have taken place due to coercion or allurement, the major conversions to Islam took place to escape the tyranny of caste system. It was not Kings who convert it but it was under the influence of Humanistic approach of Sufi saints that many converted to Islam. As Swami Vivekanand pointed out Islam came as a liberatory force for the low caste in India. Many victor Muslim kings granted mercy for defeated Hindu kings if they agreed to accept Islam. This is a miniscule number. To say that only the method of worship has changed due to conversion amongst the converts is a travesty of truth. Muslims have their own places of worship, pilgrimage, holy books and identity. The claims of current Hindutva ideologues are at odds with progenitor of Hindu Nationalism, Savarkar, for whom Muslims were a different nation.

As far as Christianity is concerned, it entered India in AD 52 with St. Thomas setting up Churches on Malabar Coast. Today their percentage (Population census 2011) is 2.30. Their work in remote Adivasis areas has got them come converts, but the overall number of 2.3% in a period of close to two millennia does not show use of any allurement or force. Surely some small denominations amongst Christian religion do claim that they want to convert, but the major denominations do not convert unless the person opts voluntarily for this. As communal politics in India developed, initially it was to convert Muslims to Hinduism by Arya Samaj. Arya Samaj started Shuddhi. At the same time Tablighi Jamat started Tanzim (organization) and Tablighi (propaganda/religious proselytization) movement in North India. Shuddhi regarded that those who converted to Islam have become impure and they need to be brought back and purification rituals need to be performed. Tanzim regarded that some Muslims have forgotten Islamic norms and they need to be taught this.

The present Ghar Wapasi campaign was started four decades ago mainly in Adivasi/Dalit areas. This was also done in the slums and aimed to convert Muslims to Hinduism. In Adivasis areas religious rituals, like giving bath in hot springs along with performance of havans (Hindu rituals) was done, after which they declared that person has become Hindu. One example of this came to light in Vednagar Agra in 2014. Some 350 Muslim pavement dwellers, who were primarily rag pickers and destitutes were told to come after taking bath. The promise was that they will be given BPL cards and ration cards. When they reached there, they were made to participate in Havan and after that they were declared to be Hindus. This was organized by Bajrang Dal and Hindu Jan Jagruti Samit, both affiliated to RSS. Amongst Muslims and Christians, the poor section is being targeted for this.

It is in this direction that many states have introduced 'Freedom of Religion' Acts which ensure that people can't choose their religion. In Many of these acts one needs permission of collectors for the same. Many pastors and priests have been beaten up on the charge of doing conversion work. On the eve of Christmas many of the traders selling Christmas ware on the pavements were beaten up on the charge of doing conversion work. On the pretext of conversion work, the most horrific act was that of burning alive of Pastor Stains with his two minor sons in Keonjhar, Orissa.

Bringing to focus Ghar Wapasi is a revival of a divisive game being played by communal organizations and its affiliates. Ghar Wapasi is a forcible conversion through intimidation. Jamat-a- hind's maulana Madani strongly condemned this view saying they are Muslims and will remain Muslims. On similar lines the campaign of love jihad has been going on. In this direction the trailer of Kerala Story 2, a very communal film for propaganda, presents as if there is an organized attempt to promote Muslim youth to woo Hindu girls for marriage and conversion. In Kerala this was investigated by police and found to be false. The trailer shows all this in a very distorted and hateful fashion. This Kerala Story 2 is yet another film made for propaganda purposes and its crudity is despicable. Like the Kerala Story which came earlier this is also based on imaginary data, far away from reality. Hadiya (Akhila who converted to Islam) case showed how fake is the narrative of allurement of Hindu girls by Muslim youth, as said it is her free choice.

This film will be an add on to the divisive politics of dominating communal organization, taking our country down to a very illiberal society where the basic principles of Fraternity are violated to the core. These calls for 'Ghar Wapasi' and films like these are a total violation of values of Indian Constitution and Indian ethos of syncretic culture which was the basis of India's emotional unity.

Middle East War Poses Grave Threat to Global Peace

UN and major powers must act decisively for immediate ceasefire: Jamiat Ulama-i-Hind

New Delhi: The President of Jamiat Ulama-i-Hind, Maulana Mahmood Madani, on Monday expressed deep concern over the rapidly escalating situation in the Middle East, warning that continued military escalation could have far-reaching consequences for global peace and stability. He said that recent aggressive and provocative actions by the United States and Israel have significantly heightened tensions in the region and pushed it towards a dangerous phase. Expressing grief over the killing of Iran's Supreme Leader, Ayatollah Ali Khamenei, his aides along with members of his family, Maulana Madani said that targeting the leadership of any sovereign country runs contrary to established international norms and treaties, and risks

dragging the world towards greater instability. He said Jamiat Ulama-i-Hind stands in solidarity with the people of Iran in this moment of grief. At the same time, he also voiced concern over Iran's actions in other countries of the region, stressing that the present circumstances demand restraint, dialogue, and collective efforts for peace.

Maulana Madani said that political and international disputes cannot be resolved through force or bloodshed, adding that military solutions only deepen hostility, fuel cycles of revenge, and result in humanitarian suffering. He urged the United Nations and the global community to play an active and effective role in securing an immediate ceasefire, de-escalation, and facilitating meaningful diplomatic engagement to prevent further destruction in the region.

Warning of wider repercussions, he said that unless global powers act with responsibility, fairness, and diplomatic wisdom, the fallout of the current crisis will extend well beyond the Middle East and threaten international stability.

Reiterating the organisation's position, Maulana Madani said Jamiat Ulama-i-Hind opposes any action that pushes humanity towards war and instability, and called for urgent efforts to resolve the crisis through dialogue and peaceful negotiations.

SUBSCRIPTION FORM
TIMES OF PEDIA

Issue	Subscription Price	Years
52	250/-	1
104	500/-	2
260	1,300/-	5
520	2,600/-	10
--	5,000/-	Life

Name :.....
Address :.....
.....
.....
Email:.....
Contact Phone No.....
for donation ☐ /life ☐ /10 yrs ☐ /5 yrs ☐ subscription
The sum of Rupees..... (Rs...../-)
through cheque/DD No.....dt.....

Fill the above form neatly in capital letters and send it to us on the following address :
Times of Pedia, K-2-A-001, Abul Fazal Enclave-I,
Jamia Nagar, Okhla, New Delhi-110025
or email : **timesofpedia@gmail.com**

Also Send us your subscription, membership, donation amount in favour of Times of Pedia, New Delhi
Punjab National Bank,Nanak Pura Branch,
New Delhi-110021
A/C No.1537002100017151, IFS Code : PUNB 0153700

"First, they ignore you, then they laugh at you, then they fight you and then you win."
- Mahatma Gandhi

ADVERTISEMENT TARIFF
TIMES OF PEDIA

Size/Insertion Single	B&W (Rs)	4 Colour (Rs)
Full Page (23.5 x 36.5 cm)	30,000/-	1,00,000/-
A4 (18.7 x 26.5 cm)	20,000/-	60,000/-
Half Page (Tall-11.6 x 36.5 cm)	18,000/-	50,000/-
Half Page (wide-23.5 x 18 cm)	8,000/-	50,000/-
Quarter Page (11.6 x 18 cm)	10,000/-	28,000/-
Visiting Card size (9.5 x 5.8 cm)	3,000/-	10,000/-

MECHANICAL DATA:

Language: English, Hindi and Urdu

Printing: Front and Back - 4 Colours , Inside pages - B&W

No. of Pages: 12 pages (more in future)

Price: Rs. 3/-

Print order: 25,000

Periodicity: Weekly

Material details: Positives/Format of your advertisements should reach us 10 days before printing.

Note: 50% extra for back page, 100% extra for front page

Please Add Rs. 10 for outstation cheques.

50% advance of total add cost would be highly appreciable, in case of one year continue add. Publication cost will reduce 50% of actual cost.

Bank transactions details of TIMES OF PEDIA
Send your subscriptions/memberships/donations etc. (Cheques/DD) in favour of TIMES OF PEDIA New Delhi
Punjab National Bank,Nanak Pura Branch , New Delhi-110021
A/C No.1537002100017151, IFS Code : PUNB 0153700

बिना ख़र्च चमकेगा चेहरा, अपनाएं पपीता-दही का आसान उपाय

पपीता एक ऐसा फल है जो न सिर्फ सेहत, बल्कि स्किन के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है. इसमें कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाए रखने में मदद करते हैं. आज इस खबर में हम आपको पपीता को दही और दही से बनने वाले कुछ आसान फेस मास्क के बारे में बताएंगे जो स्किन से जुड़ी समस्याओं को कम करने के साथ-साथ ग्लोइंग स्किन पाने में आपकी मदद करेंगे.

खूबसूरत और ग्लोइंग स्किन पाने की चाह हर किसी की होती है. इसके लिए कोई महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट पर पैसा खर्च करता है, तो कोई पार्लर में महंगे ट्रीटमेंट करवाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी किचन में मौजूद कुछ चीजें भी स्किन के लिए काफी फायदेमंद होती है. पपीता और दही से बना फेस मास्क ऐसा ही एक घरेलू नुस्खा है जो स्किन को साफ, सॉफ-ट और ग्लोइंग बनाए रखने में मदद करता है

पपीते में पैपेन नाम का एंजाइम होता है जो डेड स्किन हटाकर चेहरे पर ग्लो लाने में मदद करता है. इसमें मौजूद विटामिन C दाग-धब्बे और पिग्मेंटेशन कम करने में मदद करता है. वहीं, दही में मौजूद लैक्टिक एसिड चेहरे को हल्का एक्सफोलिएट करता है और उसे सॉफ्ट बनाता है. इससे स्किन स्मूद और फ्रेश दिखती है. यह फेस मास्क पोर्स को साफ करने में भी मदद करता है, जिससे पिंपल्स की समस्या कम हो सकती है. साथ ही इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स चेहरे को समय से पहले बूढ़ा होने से बचाते हैं और स्किन पर नेचुरल ग्लो बनाए रखते हैं.

मॉइस्चराइजिंग मास्क बनाने के लिए पपीता, दही और 1 चम्मच शहद को अच्छी तरह मिला लें. इसे चेहरे पर लगाकर 15 मिनट तक रखें, फिर ठंडे पानी से धो लें. यह मास्क ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है.

पपीता से ब्राइटनिंग मास्क बनाने के लिए पपीता में दही और एक चुटकी हल्दी मिलाएं. इस पैक को चेहरे पर 10-15 मिनट तक लगाएं और फिर अच्छी तरह धो लें. यह दाग-धब्बे कम करने और स्किन पर ग्लो लाने में मदद करता है.

पपीता से एक्सफोलिएटिंग मास्क बनाने के लिए पपीता, दही और पिसा हुआ ओट्स को आपस में अच्छी तरह मिला लें. इस मास्क को चेहरे पर लगाकर हल्के हाथों से गोल-गोल मसाज करें. 15 मिनट बाद सादे पानी से धो लें. यह मास्क डेड स्किन हटाने में मदद करता है और स्किन को सॉफ्ट बनाता है.

इन लोगों को गेहूं की रोटी से रहना चाहिए सावधान

गेहूं की रोटी कई लोगों के लिए ब्लोटिंग, थकान, और पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकती है. ग्लूटेन से जुड़ी बीमारियां जैसे सीलिएक डिजीज और नॉन-सीलिएक ग्लूटेन सेंसिटिविटी कुछ लोगों को प्रभावित करती हैं. किन लोगों को गेहूं की रोटी से परहेज करना चाहिए, इस बारे में जानेंगे.

गेहूं की रोटी लगभग हर घर में खाई जाती है जिसे दाल, सब्जी या करी के साथ काफी चाव से खाई जाती है. लेकिन कई लोगों को गेहूं की ये रोटी परेशानी खड़ी कर सकती है क्योंकि ये ब्लोटिंग और थकान संबंधित खई समस्याएं पैदा करती है. हालांकि लोगों को जब से समस्या होती है तो वो सोचते भी नहीं हैं कि रोटी से ऐसा हो सकता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कुछ लोगों को गेहूं की रोटी खाने से परहेज करना चाहिए नहीं तो उसमें मौजूद ग्लूटेन डाइजेस्टिव सिस्टम और इम्यून सिस्टम पर बुरा असर डाल सकता है. तो आइए जानते हैं, किन लोगों को ग्लूटेन की रोटी खाने से बचना चाहिए.

सीलिएक डिजीज, गेहूं में ग्लूटेन के प्रति एक ऑटोइम्यून रिएक्शन है जो आंत को नुकसान पहुंचाती है और लगभग 1 प्रतिशत भारतीयों को प्रभावित करती है. इस बीमारी का अक्सर लोगों को पता नहीं चलता. मेयो क्लिनिक की रिपोर्ट का कहना है कि इससे न्यूट्रीएंट्स ठीक से अब्जॉर्ब नहीं हो पाते जिससे एनीमिया और ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो सकती है. उन लोगों को रोटी की थोड़ी सी मात्रा भी नुकसान पहुंचा सकती है.

हेल्थलाइन के मुताबिक, नॉन-सीलिएक ग्लूटेन सेंसिटिविटी से पेट फूलना, सिरदर्द और थकान होती है.

गेहूं की रोटियों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है यानी कि वो ब्लड शुगर तेजी से बढ़ाती हैं जो डायबिटीज के मरीज़ों के लिए खराब बोता है. गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. वात्स्या का कहना है कि जिन लोगों को डायबिटीज है, उन्हें गेहूं की रोटी खाने से बचना चाहिए और इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचने के लिए ज्वार या बाजरा की रोटी खाएं.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि अधिक रिफाइंड गेहूं खाने से वजन बढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल की दिक्कतें सामने आती हैं. यदि केमिकल से उगाए गए गेहूं को रोजाना खाया जाए तो लिवर और आंत पर बोझ बढ़ जाता है.

आजकल महिलाओं में पीसीओडी (PCOD) और पीसीओएस (PCOS) की समस्या तेजी से बढ़ रही है. एक्सपर्ट्स कहते हैं, हार्मोनल असंतुलन से जूझ रही महिलाओं के लिए गेहूं का अधिक सेवन परेशानी बढ़ा सकता है. दरअसल, ग्लूटेन शरीर में सूजन पैदा कर सकता है, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या होती है और वजन घटाना मुश्किल हो जाता है.

इरिटेबल बॉउल सिंड्रोम यानी आईबीएस (IBS) वाले लोग गेहूं की रोटी आसानी से नहीं पचा सकते क्योंकि गेहूं में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्मेंटेशन पैदा करता है जिससे गैस, ब्लोटिंग (पेट फूलना) और कब्ज की समस्या होने लगती है. पेट में मरोड़ और दर्द वाले लोगों को गेहूं की रोटी खाने से बचना चाहिए. इसके लिए आप डॉक्टर से संपर्क करें.

गेहूं की जगह ज्वार, बाजरा, रागी, कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की रोटी को आजमा सकते हैं, जो पेट पर हल्के होते हैं और आसानी से पच जाते हैं.

भारतीय भोजन में गेहूं की रोटी एक प्रमुख हिस्सा है और ज्यादातर घरों में इसे रोजाना खाया जाता है। यह कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और कुछ जरूरी पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत मानी जाती है। लेकिन हर व्यक्ति के लिए गेहूं की रोटी फायदेमंद हो, यह जरूरी नहीं है। कुछ स्वास्थ्य स्थितियों में इसका सेवन नुकसानदेह भी हो सकता है।

जिन लोगों को सीलिएक रोग होता है, उनके लिए गेहूं पूरी तरह वर्जित माना जाता है। गेहूं में मौजूद ग्लूटेन नामक प्रोटीन उनके शरीर में ठीक से पच नहीं पाता, जिससे पेट दर्द, दस्त, कमजोरी और पोषक तत्वों की कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे लोगों को ग्लूटेन-फ्री आहार अपनाना पड़ता है। इसके अलावा कुछ लोगों में ग्लूटेन संवेदनशीलता पाई जाती है। उन्हें गेहूं खाने के बाद पेट फूलना, गैस, भारीपन या अपच की शिकायत हो सकती है। ऐसे मामलों में डॉक्टर की सलाह से गेहूं का सेवन कम या बंद करना बेहतर रहता है। डायबिटीज के मरीजों को भी गेहूं की रोटी सीमित मात्रा में खाने की सलाह दी जाती है।

खेल समाचार

क्या बदलेगा इतिहास? अफ्रीका-न्यूज़ीलैंड सेमीफाइनल पर सबकी नज़र

T20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल कोलकाता के ईडन गार्डन्स में बुधवार (4 मार्च) को है, जहां साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड आमने-सामने होंगे.

मुकाबला सिर्फ फाइनल के टिकट का नहीं, बल्कि कीवी टीम के लिए इतिहास बदलने का भी है. वहीं दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार (5 मार्च) को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच होना है.

साउथ अफ्रीकी टीम इस टूर्नामेंट में अब तक अजेय रही है. वहीं न्यूजीलैंड ने सुपर 8 में नेट रन रेट के आधार पर पाकिस्तान को पछाड़कर सेमीफाइनल में जगह बनाई.

कीवी टीम के कप्तान मिचेल सेंटनर के सामने बड़ी चुनौती है, और यह चुनौती है इतिहास बदलने की. क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में न्यूजीलैंड टीम कभी भी साउथ अफ्रीका को नहीं हरा पाई है.

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच कुल 19 मुकाबले हुए हैं. इनमें से 12 मैच साउथ अफ्रीका ने जीते हैं, जबकि 7 मुकाबले न्यूजीलैंड के खाते में गए हैं. आंकड़े बताते हैं कि अफ्रीकी टीम पलड़ा साफ तौर पर भारी रहा है.

एडेन मार्करम की कप्तानी में साउथ अफ्रीका पिछले टी20 वर्ल्ड कप से ही शानदार प्रदर्शन कर रहा है. 2024 में टीम फाइनल तक पहुंची थी और इस बार फिर से खिताब से सिर्फ एक जीत दूर है.वहीं मिचेल सेंटनर की अगुवाई में न्यूजीलैंड को फाइनल में जगह बनाने के लिए 19 साल का सिलसिला तोड़ना होगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि ईडन गार्डन्स की पिच पर आंकड़े हावी रहते हैं या कीवी टीम नया इतिहास रचती है.

मंधाना का जलवा: ODI में बनीं दुनिया की नंबर-1 बल्लेबाज़

आईसीसी की ताजा महिला वनडे रैंकिंग में स्मृति मंधाना दुनिया की नंबर-1 बल्लेबाज बन गई हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की अलाना किंग नंबर-1 गेंदबाज बनीं. किंग ने सोफी एक्लेस्टोन का करीब चार साल पुराना वर्चस्व खत्म किया. ऑस्ट्रेलिया-भारत सीरीज, साउथ अफ्रीका-पाकिस्तान मुकाबले और न्यूजीलैंड- जिम्बाब्वे टी20 सीरीज के बाद रैंकिंग में बड़े बदलाव देखने को मिले.

महिला क्रिकेट की ताजा ICC (International Cricket Council) रैंकिंग में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. मंगलवार (3 फरवरी) को जारी नई वनडे रैंकिंग में भारत की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना दुनिया की नंबर-1 बल्लेबाज बन गई हैं. मंधाना ने 790 रेटिंग पॉइंट्स के साथ साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वॉल्वार्ट को पीछे छोड़ा. दोनों के समान 790 अंक हैं, लेकिन हालिया प्रदर्शन के आधार पर मंधाना टॉप पर पहुंचीं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में 58 और 31 रन की पारियां खेलीं, जो उन्हें नंबर-1 तक ले जाने के लिए काफी रहीं. लॉरा को मार्च-अप्रैल में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में फिर से नंबर-1 बनने का मौका मिलेगा.

بھارت کی خارجہ پالیسی اور مودی جی کا اسرائیل دورہ! ظالم کی حمایت کر کے ہندوستان وشوگرو نہیں بن سکتا

عبدالغفار صدیقی

ہمارے وزیر اعظم کا حالیہ دورہ اسرائیل سرخیوں میں ہے۔ وہاں جا کر جس انداز میں انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، وہ موضوعِ گفتگو بن چکا ہے۔ اسرائیل کو ''فادر لینڈ'' کہنا ایک ایسا جملہ ہے جس نے بہت سے ذہنوں میں سوالات پیدا کیے ہیں۔ اس تعبیر کی اصل معنویت اور اس کے پس منظر کی وضاحت یقیناً خود وزیر اعظم ہی بہتر طور پر کر سکتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو کس نسبت اور کس رشتے سے یہ مقام دے رہے تھے۔

انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ وہ اسی دن پیدا ہوئے تھے جس دن بھارت نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا۔ اس تقارن کو انہوں نے ایک علامتی نسبت کے طور پر پیش کیا، حالانکہ اس دن دنیا کے مختلف حصوں میں بے شمار بچے پیدا ہوئے ہوں گے۔ اس ذاتی نسبت کو قومی تعلق سے جوڑنے کی معنویت کیا ہے، یہ بھی ایک قابلِ غور سوال ہے۔

تقریر کے دوران قدیم روابط، مذہبی حوالہ جات، حتیٰ کہ ہندو مذہبی متون میں اسرائیل کے تذکروں کا ذکر کیا گیا۔ ہنوکا اور دیوالی کا تقابل کرتے ہوئے ثقافتی یک رنگی کا تصور پیش کیا گیا اور دونوں قوموں کو تاریخی رشتوں میں بندھا ہوا دکھانے کی کوشش کی گئی۔ اسی موقع پر حماس کے حملے میں مارے گئے اسرائیلیوں کے لیے تعزیت کا اظہار کیا گیا اور تلمود کی اس تعلیم کا حوالہ دیا گیا کہ ''ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے۔''

بطور ایک بھارتی شہری کسی کو یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم نے اسرائیل کا دورہ کیوں کیا؟۔ بھارت اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے، دونوں ممالک کے درمیان سفارتی، دفاعی اور تجارتی معاہدے موجود ہیں، اور ہزاروں بھارتی وہاں کام کرتے ہیں۔ لیکن ایک بھارتی مسلمان کی حیثیت سے بعض جملوں نے دل کو ضرور زخمی کیا۔ اس لیے کہ بھارت کے مسلمان اور انصاف پسند غیر مسلم فلسطین میں جاری مظالم کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔

دورہ اگر سیاسی، تجارتی اور دفاعی معاملات تک محدود رہتا تو شاید یہ تکلیف پیدا نہ ہوتی۔ لیکن یک طرفہ طور پر صرف ایک فریق کے دکھ کا ذکر کرنا، اور دوسرے فریق کی طویل اذیت کو نظر انداز کر دینا، طرزِ اظہار انصاف کے تقاضوں سے ہم آہنگ محسوس نہیں ہوتا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہم اپنی قدیم متوازن خارجہ پالیسی سے دور تو نہیں جا رہے؟

جب ہندوستان آزاد ہوا تو اس کے سامنے صرف سرحدوں کا سوال نہیں تھا، بلکہ اخلاقی شناخت کا سوال بھی تھا۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے خارجہ پالیسی کی جو بنیاد رکھی، وہ محض سفارتی حکمتِ عملی نہ تھی بلکہ ایک اخلاقی اعلان تھا۔ 1947ء میں اقوام متحدہ میں فلسطین کی تقسیم کے منصوبے کے خلاف ہندوستان نے ووٹ دیا۔ یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا۔ اس وقت دنیا بڑی طاقتوں کے دباؤ میں تھی، مگر ہندوستان نے اصولی مؤقف اختیار کیا کہ کسی قوم کی سرزمین اس کی مرضی کے بغیر تقسیم نہیں کی جا سکتی۔

1950ء میں ہندوستان نے اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم ضرور کیا، مگر مکمل سفارتی تعلقات قائم نہ کیے۔ اس کے برعکس 1974ء میں فلسطین لبریشن آرگنائزیشن (پی ایل او) کو فلسطینی عوام کا نمائندہ تسلیم کیا گیا۔ 1988ء میں جب فلسطینی ریاست کے قیام کا اعلان ہوا تو ہندوستان ان ابتدائی ممالک میں شامل تھا جنہوں نے اسے تسلیم کیا۔ یہ فیصلے نہرو کے بعد اندرا گاندھی اور راجیو گاندھی کے ادوار میں بھی برقرار رہے۔ غیر وابستہ تحریک میں ہندوستان ہمیشہ فلسطینی حقِ خودارادیت کا وکیل بنا رہا۔

یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ 1990ء کی دہائی کے بعد سب کچھ یکسر بدل گیا۔ 1992ء میں پی وی نرسمہا راؤ کی حکومت نے اسرائیل سے مکمل سفارتی تعلقات قائم کیے، مگر فلسطین کی حمایت ترک نہیں کی۔ اٹل بہاری واجپئی کے دورِ حکومت (1998ء تا 2004ء) میں اسرائیل کے ساتھ دفاعی تعلقات میں وسعت آئی، 2003ء میں اسرائیلی وزیر اعظم ایریل شیرون ہندوستان آئے، مگر اسی زمانے میں یاسر عرفات کا خیر مقدم بھی ہوا اور اقوام متحدہ میں فلسطین کے حق میں ہندوستان کی رائے برقرار رہی۔ یہ ایک توازن تھا ایک طرف قومی مفاد، دوسری طرف اصولی روایت۔ اب سوال یہ ہے کہ نریندر مودی کے دور میں کیا بدلا؟ 2017ء میں نریندر مودی اسرائیل کا دورہ کرنے والے پہلے بھارتی وزیر اعظم بنے۔ اس سے پہلے بھارتی وزرائے اعظم اسرائیل اور فلسطین دونوں کا دورہ ایک ساتھ کیا کرتے تھے تاکہ توازن کا تاثر برقرار رہے۔ مگر مودی نے اس روایت کو توڑ دیا۔ بعد میں فلسطین کا علیحدہ دورہ ضرور ہوا، لیکن سفارتی علامتیں بڑی معنی خیز ہوتی ہیں۔ سیاست میں اشارے بھی پیغام ہوتے ہیں۔

یہاں ایک اور پہلو بھی اہم ہے۔ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) کی فکری بنیاد ہندوتو قومیت پر ہے۔ اس کا تصورِ قومیت مذہبی و تہذیبی شناخت کو مرکزی حیثیت دیتا ہے۔ دوسری جانب صہیونی تحریک بھی ایک مذہبی و نسلی شناخت کی بنیاد پر ریاست کے قیام کا نظریہ پیش کرتی رہی ہے۔ کئی مبصرین نے اس نظریاتی مماثلت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دونوں تحریکیں اپنے اپنے اکثریتی مذہبی تشخص کو ریاستی طاقت کا محور سمجھتی ہیں۔ اگرچہ دونوں کی تاریخی اور جغرافیائی صورت حال مختلف ہے، لیکن فکری قربت کے تاثر سے انکار ممکن نہیں۔

لیکن کیا مودی حکومت اسرائیل سے تعلقات صرف نظریاتی ہم آہنگی کی بنیاد پر مضبوط کر رہی ہے؟ یا اس کے پیچھے دیگر عوامل اور وجوہات بھی کارفرما ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ نظریاتی اور فکری ہم آہنگی ،مسلمانوں کے تئیں صیہونیت اور فاشزم کی مشترکہ ذہنیت کے علاوہ امریکہ کی خوشنودی کا حصول، چین اور پاکستان کے تناظر میں دفاعی معاہدے، اور اسرائیل کی جدید زراعتی ٹیکنالوجی سے استفادہ بھی ان تعلقات کی معقول وجوہات ہو سکتی ہیں۔

مگر اصل سوال یہ ہے کہ کیا اس نئی قربت کا کوئی منفی تاثر ہندوستانی مسلمانوں پر پڑ رہا ہے؟ ظاہر ہے اس کا جواب ہاں میں ہے۔ اس لیے کہ ہندوستانی مسلمان فلسطین پر اسرائیلی جارحیت کی کھل کر مذمت کرتے ہیں، اسرائیلی پالیسیاں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ ہندوستان کے بیس کروڑ سے زائد مسلمان اس ملک کے برابر کے شہری ہیں۔ انہوں نے آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیا، آئین کی تشکیل میں کردار ادا کیا، اور آج بھی ہر شعبے میں موجود ہیں۔ ملک کی بدلتی خارجہ پالیسی سے مسلمانوں کا فکر مند ہونا فطری ہے۔ اگر خارجہ پالیسی کا رخ اس انداز میں بدلے کہ داخلی سطح پر ایک طبقہ خود کو غیر محفوظ محسوس کرے، تو یہ محض سفارتی مسئلہ نہیں رہتا بلکہ سماجی ہم آہنگی کا مسئلہ بن جاتا ہے۔

ہندوستان کی بدلتی ہوئی خارجہ پالیسی کے تناظر میں ہندوستانی مسلمان کیا کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے، جذباتی ردِ عمل کے بجائے آئینی راستہ اختیار کریں۔ احتجاج ہو تو پر امن ہو، مطالبات ہوں تو آئینی زبان میں ہوں۔ دوسرا، سیاسی شرکت بڑھائیں۔ ووٹ کی طاقت جمہوریت میں سب سے بڑی طاقت ہے۔ تیسرا، تعلیمی و معاشی میدان میں مضبوطی حاصل کریں تاکہ کوئی بھی بیانیہ انہیں کمزور ثابت نہ کر سکے۔ چوتھا، بین المذاہب مکالمہ بڑھائیں۔ ہندو، سکھ، عیسائی سب اس ملک کے شہری ہیں۔ باہمی اعتماد ہی کسی بھی تقسیم کو ناکام بناتا ہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت پر یہ بات واضح رہنی چاہئے کہ خارجہ پالیسی میں قومی مفاد اہم ہے، مگر داخلی اتحاد اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ ہندوستان کی اصل طاقت اس کی تکثیریت ہے۔ اگر دنیا میں ہندوستان کو ایک عظیم جمہوریت کے طور پر پیش کرنا ہے تو اسے اپنے اندر ہر طبقے کے اعتماد کو مضبوط رکھنا ہوگا۔ تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصولی مؤقف اور عملی مفاد میں توازن ممکن ہے۔ نہرو کے دور میں بھی عالمی دباؤ تھا، واجپئی کے زمانے میں بھی علاقائی چیلنج تھے، مگر فلسطین کی حمایت اور اسرائیل سے تعلقات دونوں ساتھ چلتے رہے۔ آج بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہئے کہ ظالم کی حمایت کر کے ہم وشوگرو نہیں بن سکتے۔ اسرائیل کسی کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں یوں تو بہت سے خود غرض ممالک ہیں مگر اسرائیل ان میں سرفہرست ہے۔

سوال کسی ایک دورے کا نہیں، بلکہ اس سمت کا ہے جس طرف ملک بڑھ رہا ہے۔ کیا ہم طاقت کی سیاست کو اخلاق کی سیاست پر غالب آنے دیں گے؟ یا ہم وہی ہندوستان بنے رہیں گے جو مظلوم کے حق میں آواز اٹھاتا تھا، اور اپنے اندر سب کو ساتھ لے کر چلتا تھا؟ فیصلہ صرف حکومت کا نہیں، عوام کا بھی ہے۔ اگر ہم آئین، جمہوریت اور باہمی احترام کو مضبوط رکھیں گے تو کوئی بھی خارجہ پالیسی داخلی تقسیم کا سبب نہیں بن سکے گی۔ ہندوستان کی اصل پہچان اس کی گنگا جمنی تہذیب ہے۔ اسے برقرار رکھنا ہی سب سے بڑا قومی مفاد ہے۔

وفیات۔۔آیت اللہ علی خامنہ ای: ایک دور کا خاتمہ

اسد مرزا

آیت اللہ علی خامنہ ای (1939-2026)، ایران کے دوسرے سپریم لیڈر تھے، وہ 28 فروری 2026 کو تہران پر امریکی اور اسرائیل کے مربوط فضائی حملوں کے دوران ہلاک ہو گئے۔ ان کی ہلاکت کی تصدیق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ابتدائی اعلان کے بعد یکم مارچ 2026 کو ایران کے سرکاری میڈیا نے بھی کی ہے۔

خامنہ ای کو ''آپریشن ایپک فیوری'' کے نام سے تعبیر کیے گئے کہ ایک امریکہ۔اسرائیل مشترکہ آپریشن میں ان کے دفتر میں ہلاک کیا گیا۔ ان کے ساتھ اسلامی انقلابی گارڈ کور (IRGC) کے کمانڈر اور وزیر دفاع سمیت کئی دیگر اعلیٰ عہدے دار بھی مارے گئے۔

ایران نے 40 روزہ سرکاری سوگ اور سات دن کی تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔ آیت اللہ علی خامنہ ای کا کوئی نامزد جانشین نہیں ہے۔ ایرانی آئین کے تحت صدر، عدلیہ کے سربراہ اور گارڈین کونسل کے رکن پر مشتمل کونسل عارضی طور پر قیادت کے فرائض سنبھالے گی۔

آیت اللہ علی خامنہ ای نے 1989 سے 2026 تک 36 سال تک اسلامی جمہوریہ ایران کے سپریم لیڈر کے طور پر خدمات انجام دیں، جس سے وہ مشرق وسطیٰ میں سب سے طویل عرصے تک برسر اقتدار رہنے والے حکمراں بنے۔

وہ مشہد میں 1939 میں پیدا ہوئے تھے، وہ 1979 کے اسلامی انقلاب کی ایک اہم شخصیت تھے اور 1981 سے 1989 تک ایران کے صدر کے طور پر خدمات انجام دیں۔ ان کی مذہبی وابستگی اس وقت واضح تھی جب وہ 11 سال کی عمر میں عالم بنے۔ انہوں نے عراق اور ایران کے مذہبی دارالحکومت قم میں تعلیم حاصل کی۔ ان کے والد، نسلی آذری نسل کے ایک مذہبی اسکالر، ایک روایتی مولوی تھے جو مذہب اور سیاست کو ملانے کے مخالف تھے۔ اس کے برعکس ان کے بیٹے نے اسلامی انقلابی مقصد کو قبول کیا۔

1963 میں، خامنہ ای نے پہلی بار جیل میں گزاری جب انہیں 24 سال کی عمر میں سیاسی سرگرمیوں کے لیے حراست میں لیا گیا۔ اس سال کے آخر میں انہیں مشہد میں 10 دن تک قید رکھا گیا، جہاں ان کی سرکاری سوانح عمری کے مطابق ان پر شدید تشدد بھی کیا گیا۔ ایک ماہر اسلامیات، ان کی فکر مغرب مخالف، خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ان کی گہری دشمنی اور اسلامی اصولوں کے ساتھ ان کی غیر متزلزل وابستگی کے ذریعہ بیان کی جا سکتی ہے۔

آیت اللہ علی خامنہ ای کی 36 سالہ حکمرانی نے ایران کو ایک طاقتور امریکہ مخالف قوت کے طور پر بنایا، جس نے پورے مشرق وسطیٰ میں اپنی فوجی طاقت کو پھیلایا۔

انہیں پہلے تو سیاسی طور پر کمزور اور غیر فیصلہ کن قرار دے کر مسترد کر دیا گیا، خامنہ ای اسلامی جمہوریہ ایران کی بنیاد رکھنے والے کرشماتی آیت اللہ روح اللہ خمینی کی موت کے بعد سپریم لیڈر کے عہدے کے لیے ایک غیر متوقع انتخاب نظر آئے۔ لیکن خامنہ ای کا ملک کے اقتداری ڈھانچے کے عروج پر پہنچنا ان کی ملکی معاملات پر سخت گرفت اور آیت اللہ خمینی کی فکر کو فروغ دینے کی وجہ سے ممکن ہوا۔

خامنہ ای نے طویل عرصے سے اس بات کی تردید کی کہ ایران کے جوہری پروگرام کا مقصد جوہری ہتھیار بنانا ہے، جیسا کہ مغرب کا دعویٰ تھا۔ 2015 میں انہوں نے محتاط انداز میں عالمی طاقتوں اور اصلاح پسند صدر حسن روحانی کی حکومت کے درمیان ایک جوہری معاہدے کی حمایت کی جس نے پابندیوں میں نرمی کے بدلے ملک کے جوہری پروگرام کو روک دیا تھا۔ مشکل سے جیتنے والے معاہدے کے نتیجے میں ایران کی اقتصادی اور سیاسی تنہائی کو جزوی طور پر ختم کر دیا گیا تھا۔ خامنہ ای کی امریکہ کے خلاف دشمنی غیر معمولی تھی، 2018 میں اس میں شدت آئی جب ٹرمپ کی پہلی انتظامیہ نے جوہری معاہدے سے دستبرداری اختیار کی اور ایران کی تیل اور جہاز رانی کی صنعتوں کا گلا گھونٹنے کے لیے دوبارہ ایران پر پابندیاں عائد کر دیں تھیں۔ آیت اللہ نے اپنے پورے دور اقتدار میں واشنگٹن پر تنقید جاری رکھی اور 2025 میں امریکی صدر کے طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری مدت کے آغاز کے بعد اس میں مزید شدت آئی۔

ایران کے سابق شاہ کے زوال کے بعد، خامنہ ای نے اسلامی جمہوریہ میں انہوں نے کئی عہدے سنبھالے۔ نائب وزیر دفاع کے طور پر، وہ فوج کے قریب ہو گئے اور پڑوسی ملک عراق کے ساتھ 1980-88 کی جنگ میں ایک اہم شخصیت تھے، جس میں ایک اندازے کے مطابق مجموعی طور پر دس لاکھ افراد کی جانیں گئیں۔

وہ ایک ماہر خطیب بھی تھے گو کہ ان کے پاس آیت اللہ خمینی جیسی مقناطیسی شخصیت نہیں تھی لیکن اس کے باوجود وہ دو مرتبہ ایران کے صدر کے عہدے پر فائز بھی رہے اور ساتھ ہی ایرانی آئی آر جی سی کے ساتھ تعلقات استوار کر کے ایران پر اپنے اقتدار کو قائم رکھنے میں کامیاب بھی رہے۔

ساتھ ہی پابندیوں کے زمانے میں ایرانی معیشت کو انہوں نے کمزور نہیں پڑنے نہیں دیا۔ خامنہ ای نے خطے میں ایرانی اثر و رسوخ کو بڑھایا، عراق اور لبنان میں شیعہ ملیشیا کو بااختیار بنایا، اور شام میں ہزاروں فوجیوں کو تعینات کر کے اس وقت کے صدر بشار الاسد کو آگے بڑھایا۔ خامنہ ای کی حکمرانی میں، ایران اور اسرائیل نے برسوں تک شیڈو جنگ لڑی، جس کے دوران اسرائیل نے تہران کے جوہری سائنسدانوں اور پاسداران انقلاب کے کمانڈروں کو قتل کیا۔

ماضی میں امریکہ اور اسرائیل نے خبردار کیا تھا کہ اگر ایران نے اپنے جوہری اور بیلسٹک میزائل پروگرام کو آگے بڑھایا تو وہ دوبارہ حملہ کریں گے اور ہفتے کے روز انہوں نے کئی دہائیوں میں ایرانی اہداف پر سب سے زیادہ مہلک حملہ کیا۔

سفارتی محاذ پر، خامنہ ای نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کو ہمیشہ مسترد کیا تھا۔ ان کی دلیل تھی کہ واشنگٹن نے خطے میں فرقہ وارانہ جنگ کو ہوا دینے کے لیے اسلامک اسٹیٹ جیسے سخت گیر گروہوں کی حمایت کی ہے۔

تمام ایرانی حکام کی طرح، خامنہ ای نے جوہری ہتھیاروں کو تیار کرنے کے کسی ارادے سے انکار کیا اور 1990 کی دہائی کے وسط میں جوہری ہتھیاروں کی ''پیداوار اور استعمال'' کے بارے میں اسلامی حکم یا فتویٰ جاری کیا تھا۔ مرحوم آیت اللہ نے اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کے ساتھ ساتھ ملک میں خاص طور پر نوجوان نسلوں کے درمیان بڑھتے ہوئے اختلاف کے درمیان اسلامی جمہوریہ کو اس کے سب سے نازک دوڑ میں الوداع کہا ہے۔

दिल्ली में 'सशक्त नारी, समृद्ध दिल्ली' कार्यक्रम, महिलाओं को 4 बड़ी सौग़ातें

नई दिल्ली। (टॉप ब्यूरो) होली के मौके पर दिल्ली सरकार आज राजधानी की महिलाओं और बेटियों को चार बड़ी सौगातें देने जा रही है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम 'सशक्त नारी, समृद्ध दिल्ली' में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ करेंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, इन पहलों से लाखों परिवारों और महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा।

सरकार 'लाडली योजना' को विस्तारित और सुदृढ़ रूप में 'दिल्ली लखपति बिटिया योजना' के तौर पर लागू कर रही है। नई व्यवस्था के तहत बालिका के नाम पर विभिन्न चरणों में कुल 56 हजार रुपये जमा किए जाएंगे, जो ब्याज सहित 21 वर्ष की आयु तक एक लाख रुपये से अधिक हो सकते हैं। पूर्व में जन्म और शैक्षणिक पड़ावों पर दी जाने वाली राशि को अब अधिक व्यवस्थित और डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से संचालित किया जाएगा। लंबित परिपक्वता राशि भी लाभार्थियों के खातों में भेजी जाएगी।

महिलाओं की सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए 'पिंक कार्ड' (नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड-एनसीएमसी) की शुरुआत की जाएगी। यह कार्ड दिल्ली निवासी महिलाओं को डीटीसी बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा देगा, जबकि मेट्रो और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में एक ही स्मार्ट कार्ड से भुगतान संभव होगा। कार्ड जारी करने के लिए करीब 50 केंद्र स्थापित किए जाएंगे और इसे आधार व मोबाइल नंबर से लिंक किया जाएगा। इसके अलावा, होली और दिवाली पर राशन कार्ड धारक परिवारों को प्रति वर्ष दो मुक्त एलपीजी सिलेंडर देने की योजना का भी औपचारिक शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक, लगभग 15.5 लाख परिवारों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सिलेंडर की मौजूदा कीमत के बराबर राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी योजनाओं की निगरानी पूरी तरह डिजिटल प्रणाली से की जाएगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंचे। अधिकारियों के अनुसार, पिंक कार्ड व्यवस्था से महिलाओं की दैनिक यात्रा अधिक सुरक्षित, आसान और किफायती होगी। प्रत्येक यात्रा का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा, जिससे नकद लेन-देन में कमी आएगी और परिवहन व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित बनेगी।

लखपति बिटिया योजना के अंतर्गत पात्र बालिकाओं का पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे आवेदन प्रक्रिया सरल होगी और किसी प्रकार की बिचौलिया व्यवस्था खत्म होगी। योजना का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, स्कूल छोड़ने की दर कम करना और परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना से खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राहत मिलने की उम्मीद है। त्योहारों के समय बढ़ते घरेलू खर्च के बीच यह सहायता परिवारों के बजट को संतुलित करने में सहायक होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है और भविष्य में भी ऐसी जनहितकारी योजनाएं लाई जाती रहेंगी, ताकि राजधानी की महिलाएं आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें।

ख़ामेनेई की मौत की ख़बर के बाद जंतर-मंतर पर प्रदर्शन, अमेरिका-इज़रायल के ख़िलाफ नारेबाज़ी

नई दिल्ली। (टॉप ब्यूरो) ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की कथित मौत की खबर सामने आने के बाद राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में विरोध-प्रदर्शन हुए। दिल्ली के जंतर-मंतर पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए और अमेरिका व इजरायल के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कई लोग भावुक नजर आए और उन्होंने इसे षड्यंत्र करार दिया।

जंतर-मंतर पर जुटी भीड़ में शामिल लोगों ने काले कपड़े पहनकर शोक व्यक्त किया। प्रदर्शनकारियों के हाथों में अयातुल्ला खामेनेई की तस्वीरें और काले झंडे थे। इजरायल और अमेरिका के विरोध में नारे लगाए गए। कुछ महिलाएं रोती हुई भी दिखाई दीं। प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

इसी क्रम में दक्षिण-पूर्वी दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बाहर भी लोगों की भीड़ जमा हुई। जानकारी के अनुसार, वहां शोक सभा आयोजित की गई और विशेष नमाज अदा की गई। छात्र संगठनों और कुछ स्थानीय नेताओं ने भी प्रदर्शन में भाग लिया और ईरानी नेता के प्रति समर्थन जताया।

राजधानी के अलावा लखनऊ और जम्मू के कुछ इलाकों में भी विरोध-प्रदर्शन की खबरें सामने आईं। लखनऊ में शिया समुदाय के सदस्यों ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारेबाजी की और घटना पर कड़ा विरोध जताया।

یکجہتی کی پروقار افطار تقریب: امید، استقامت اور انصاف کا عہد

نئی دہلی:ایسوسی ایشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس (اے۔ پی۔ سی۔ آر) نے دہلی کے کانسٹی ٹیوشن کلب میں"افطار و ڈنر برائے یکجہتی: امید، استقامت اور انصاف" کے عنوان سے ایک باوقار تقریب کا انعقاد کیا۔ اس شاندار تقریب میں سیاسی قیدیوں کے اہلِ خانہ، سینئر وکلاء، نامور سماجی کارکنان، معروف صحافیوں، اہم سول سوسائٹی کے نمائندوں اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی معزز شخصیات نے شرکت کی اور اجتماعی یادداشت اور عزمِ نو کا مظاہرہ کیا۔ رمضان المبارک کی روحانی فضا میں منعقدہ اس افطار تقریب کا محور جیلوں میں قید و بند کی صعوبتوں سے گزر رہے اُن اسیرانِ ضمیر اور ان کے خاندانوں سے اظہارِ یکجہتی تھا جو طویل عرصے سے آزمائشوں، معاشی دباؤ اور سماجی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ محض افطار کی ایک رسمی نشست بھر ہی نہیں تھی بلکہ انصاف، انسانی وقار اور آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے مشترکہ اخلاقی ذمہ داری کی تجدید تھی۔ معروف سماجی کارکن گوتم نولکھا نے اپنے خطاب میں اجتماعی جدوجہد کی ناگزیر اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ"سول سوسائٹی مردہ نہیں تصور کی جائیگی۔ جب تک ایسے لوگ اور اس طرح کی تقریب منعقد ہوتی رہیں گی، یقیناً ابھی ہم زندہ ہیں۔"ان کے یہ الفاظ حاضرین کے لیے حوصلے اور استقامت کا پیغام ثابت ہوئے۔ جیل میں قید ڈاکٹر عمر خالد کے والد اور معروف صحافی ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے متاثرہ خاندانوں کے صبر و استقامت کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایسے مواقع نہ صرف اخلاقی اور جذباتی سہارا فراہم کرتے ہیں بلکہ یہ واضح اعلان بھی ہوتے ہیں کہ ان کی جدوجہد نہ تو نظرانداز کی جاسکتی ہے اور نہ ہی فراموش کی جائے گی۔ سری نگر سے رکنِ پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی نے اپنے پُراثر خطاب میں تقریب کے ظاہری پہلوؤں کے بجائے اس کے اخلاقی جوہر پر توجہ مرکوز کی۔ انہوں نے کہا کہ اس تقریب کی اصل قدر کھانے یا سماجی میل جول میں نہیں ہے بلکہ اس مشترکہ مقصد میں ہے جس نے سب کو یکجا کیا ہے۔ انہوں نے اُن افراد کی قربانیوں کا ذکر کیا جو حق و صداقت کی آواز بلند کرنے کی پاداش میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ موجودہ خوف اور غیر یقینی کی فضا کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے اعتراف کیا کہ قدم بعض اوقات لڑکھڑاتے ہیں، مگر انصاف کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہونا اور جدوجہد جاری رکھنا ایک اخلاقی فریضہ ہے۔ تقریب نے اس حقیقت کو بھی اجاگر کیا کہ ہر اسیر کے پیچھے ایک خاندان ہوتا ہے جو جذباتی اذیت، معاشی دشواریوں اور سماجی چیلنجز سے نبرد آزما ہے۔ ان خاندانوں کے لیے علامتی طور پر دسترخوان پر نشستیں محفوظ رکھ کر اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ قید خانوں کی دیواریں یادداشت اور یکجہتی کو محدود نہیں کرسکتیں ہیں۔ اے۔ پی۔ سی۔ آر کے نیشنل سکریٹری ندیم خان نے کہا کہ ہمارا کوشش اس عزم کا اعادہ ہے کہ وہ آئینی اقدار، انسانی حقوق اور انصاف کے لیے اپنی پرامن اور جمہوری جدوجہد جاری رکھے، اور ہر اس خاندان کے ساتھ کھڑی رہے جو ناانصافی کا سامنا کر رہا ہے۔ تقریب میں دہلی کے سابق لیفٹیننٹ جنرل نجیب جنگ۔ پٹنہ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس اقبال احمد انصاری۔ رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر محمد جاوید، رکن پارلیمنٹ مولانا محب اللہ ندوی۔ انڈین مسلمس فار سول رائٹس کے چیئرمین اور سابق رکن محمد ادیب، سابق رکن پارلیمنٹ کنور دانش علی۔ سابق سفیر اور رکن پارلیمنٹ میم افضل۔ سابق سفارتکار ڈاکٹر اشوک شرما، پلاننگ کمیشن کی سابق رکن سید سیدین حمید، سابق میجر جنرل جاوید اقبال خان اور جماعت اسلامی ہند کے نائب صدر ملک معتصم خان سمیت درجنوں اہم شخصیات کی موجودگی نے تقریب میں اسیران کے اہل خانہ کی نہ صرف حوصلہ افزائی کی بلکہ اے۔ پی۔ سی۔ آر کی کوششوں کی جم کر تعریف بھی کی۔

ایران کے معاملے پر حکومتی خاموشی افسوسناک: ڈاکٹر نریش کمار

نئی دہلی: دہلی کانگریس کے ترجمان ڈاکٹر نریش کمار نے ایران پر حالیہ حملے کے تناظر میں حکومت ہند کی خاموشی کو افسوسناک قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کے قتل کو تین دن گزر جانے کے باوجود سرکاری سطح پر کوئی واضح بیان سامنے نہ آنا ہندوستان کی سفارتی روایت کے برخلاف ہے۔ ڈاکٹر نریش کمار نے کہا کہ ایران اور ہندوستان کے تعلقات تاریخی، ثقافتی اور اقتصادی بنیادوں پر استوار رہے ہیں۔ انہوں نے یاد دلایا کہ مختلف بین الاقوامی معاملات میں ایران نے ہندوستان کے مؤقف کی حمایت کی ہے، لہٰذا موجودہ صورتحال میں حکومت کو بروقت اور متوازن ردِعمل دینا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان جیسے بڑے جمہوری ملک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہم عالمی واقعات پر واضح مؤقف اختیار کرے، تاکہ علاقائی استحکام اور بین الاقوامی اعتماد برقرار رہے۔ انہوں نے زور دیا کہ خارجہ پالیسی میں شفافیت اور فعال سفارت کاری وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نریش کمار نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ ہندوستان کو اپنی خارجہ پالیسی میں شفافیت اور بروقت مکالمے کو ترجیح دینی چاہیے۔ انہوں نے زور دیا کہ بین الاقوامی واقعات پر واضح مؤقف اختیار کرنے سے نہ صرف ہمارے دوست ممالک کے ساتھ اعتماد مضبوط ہوتا ہے بلکہ ہندوستان کی عالمی شبیہ ایک ذمہ دار اور فعال جمہوریت کے طور پر ابھرتی ہے۔ ایسے میں ایران میں پیش آئے اس افسوسناک واقعہ پر ہندوستان کا متوازن، حساس اور فوری ردعمل ضروری تھا۔

امت کو قرآن سے وابستہ کرنا جمعیۃ علماء ہند کی بنیادی تحریک: مولانا محمد حکیم الدین قاسمی

نئی دہلی: جمعیۃ علماء ہند کے صدر دفتر آئی ٹی او، نئی دہلی کے فدائے ملت (ہند ہال) میں 10 روزہ تراویح کے دوران حافظ ابوبکر، فرزند مولانا محمد حکیم الدین قاسمی (ناظم عمومی جمعیۃ علماء ہند) نے بحمد اللہ قرآن مجید مکمل کیا۔ سامع کے طور پر مولانا کلیم الدین قاسمی، انچارج مہمان خانہ دفتر جمعیۃ علماء ہند نے ذمہ داری ادا کی۔ اس موقع پر ایک مختصر مگر باوقار تقریب اور دعائیہ محفل منعقد ہوئی جس میں دہلی کے ممتاز علماء کرام، جمعیۃ کے ذمہ داران اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر اپنے کلیدی خطاب میں ناظمِ عمومی جمعیۃ علماء ہند مولانا محمد حکیم الدین قاسمی نے ماہِ رمضان کی روحانی اہمیت اور قرآنِ مجید سے مضبوط تعلق کی ضرورت پر مختصر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ جمعیۃ علماء ہند ایک طویل عرصہ سے معاشرے کو قرآن سے جوڑنے کی جدوجہد کر رہی ہے، اور یہ وہی مشن ہے جس کا تصور حضرت شیخ الہندؒ نے مالٹا سے واپسی کے بعد امت کے سامنے پیش کیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جمعیۃ علماء ہند امت میں اتحاد و اتفاق، قرآن کے ساتھ عملی وابستگی اور صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے سرگرم عمل ہے، تاکہ دینِ حق کا قیام ہو اور معاشرہ خودی اور پوری انسانیت کے لیے مفید ثابت ہو سکے۔ جمعیۃ علماء ہند اس مقصد کے لیے درس قرآن کی مہم چلائی ہے۔ مولانا حکیم الدین قاسمی نے جمعیۃ علماء صوبہ دہلی کے ذمہ داران کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ جمعیۃ کے مشن کو مزید آگے بڑھائیں، مقامی سطح پر تنظیم کو مضبوط بنائیں اور ملت کے ہر فرد کے لیے نفع بخش سرگرمیوں کو فروغ دیں۔

یوتھ کانگریس کی 'شرٹ لیس تحریک' قابل ستائش اور تاریخی ہے: عمران پرتاپ گڑھی

نئی دہلی: انڈین یوتھ کانگریس کے رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس کے راجیہ سبھا رکن اور محکمہ اقلیتی امور کے چیئرمین عمران پرتاپ گڑھی نے بی جے پی حکومت کی پالیسیوں کی مخالفت کی اور انڈین یوتھ کانگریس کی 'شرٹ لیس تحریک' کی تعریف کی۔ عمران پرتاپ گڑھی نے کہا کہ بغیر شرٹ کے یہ احتجاج انہیں بابائے قوم مہاتما گاندھی کی یاد دلاتا ہے، اور پولیس کو یاد رکھنا چاہیے کہ حکومتیں آتی جاتی ہیں، لیکن شہریوں کو اپنے حقوق کے لیے پرامن احتجاج کرنے سے نہیں روکا جانا چاہیے۔ یہ حق ہمارے آئین کی ضمانت ہے۔ عمران پرتاپ گڑھی نے کہا کہ جب بھی حکومت اپنی ہٹ دھرمی اور غلط پالیسیوں کے ذریعے ہمارے حقوق کو پامال کرنے کی کوشش کرے، تو ملک بھر کے شہریوں کو حکومت کو بیدار کرنے اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے احتجاج کرنا چاہیے۔ انہوں نے زور دیا کہ سبھی کو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے لکھے ہوئے آئین کی حفاظت کرنی چاہیے۔ عمران پرتاپ گڑھی نے اپنی تقریر میں کہا کہ اگر حکومت بے شرم، انتظامیہ لاپرواہ، میڈیا بے معنی اور وزیر اعظم بیکار ہو جائیں تو یوتھ کانگریس بھی شرٹ لیس ہو کر اپنا احتجاج ظاہر کر سکتی ہے۔ کانگریس ایم پی عمران پرتاپ گڑھی نے یوتھ کانگریس لیڈروں کے اس احتجاج کو احتجاج کا مکمل طور پر صحیح طریقہ بتایا اور اس تحریک کا

گاندھی جی کی تحریک سے موازنہ کیا۔ عمران پرتاپ گڑھی نے انڈین یوتھ کانگریس کے ہیڈکوارٹر میں نوجوان کانگریسی لیڈروں سے خطاب کرتے ہوئے موجودہ سیاسی صورتحال اور بین الاقوامی اثر و رسوخ (امریکہ وغیرہ) کا بھی ذکر کیا اور پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ اگر ہمارے نوجوان نریندر مودی جی کی قیادت میں بغیر شرٹ کے احتجاج کرتے ہیں تو رات کو ان کے گھروں پر چھاپے مارنے کے لیے پولیس بھیجی جاتی ہے۔ انہوں نے ایسا کیا کیا ہے کہ رات کو جھوٹے مقدمات بنا کر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ کانگریس لیڈر عمران پرتاپ گڑھی نے یوتھ کانگریس سے کہا کہ انہوں نے بغیر شرٹ کے احتجاج کر کوئی جرم نہیں کیا ہے اور حکومت و پولیس کو بھی سمجھ لینا چاہئے کہ ظلم کو برداشت کرنا اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا جرم کرنا۔ انڈین یوتھ کانگریس کے صدر ادے بھانو چب کی ضمانت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں ملک کی عدلیہ پر پورا بھروسہ ہے اور عدلیہ نے حکومت و پولیس کی ملی بھگت سے آمریت کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ انھیں جواب دے دیا ہے کہ جمہوریت میں احتجاج کرنا اور اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہمارا حق ہے۔ عمران پرتاپ گڑھی نے کانگریس کے تمام وکلاء کو مبارکباد بھی دی۔ انہی کی کوششوں اور وکالت سے بی جے پی حکومت کو شکست ہوئی اور عدلیہ نے ضمانت دے کر راحت فراہم کی۔

आरोपमुक्ति के बाद जंतर-मंतर पर आप की मेगा रैली

नई दिल्ली। (टॉप ब्यूरो) कथित आबकारी नीति मामले में निचली अदालत से आरोपमुक्त किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) आज जंतर-मंतर पर मेगा रैली आयोजित करेगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इस जनसभा को संबोधित करेंगे। अदालत के फैसले के बाद यह उनकी पहली बड़ी सार्वजनिक रैली मानी जा रही है।

पार्टी नेताओं के अनुसार, रैली में संगठन के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बताया कि कार्यक्रम के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त हो गई है और जनसभा तय समय पर आयोजित होगी। इससे पहले अनुमति को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, जिस पर पार्टी ने आपत्ति जताई थी।

अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया मंच 'एम्स' पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि शांतिपूर्ण रैली करना और अपनी बात रखना लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने संकेत दिया था कि कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की गई, हालांकि बाद में प्रशासन की ओर से अनुमति दे दी गई।

गौरतलब है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को कथित आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित अन्य आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया था। इस मामले ने दिल्ली की राजनीति में लंबे समय तक विवाद पैदा किया और सियासी हलकों में व्यापक चर्चा का विषय बना रहा। आज की रैली को अदालत के फैसले के बाद शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है।

अरावली में बने धार्मिक स्थलों को वन विभाग का नोटिस

फरीदाबाद। (टॉप ब्यूरो) अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में बने धार्मिक स्थलों और अन्य अवैध निर्माणों को लेकर वन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। विभाग की ओर से संबंधित स्थलों पर नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर अवैध ढांचे हटाने के निर्देश दिए गए हैं। चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय सीमा में निर्माण नहीं हटाए जाने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। कुछ मंदिर परिसरों में नोटिस चस्पा भी किए गए हैं।

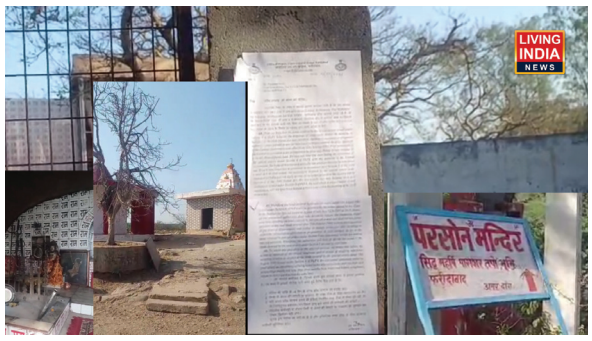

वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, अरावली वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण पीएलपीए एक्ट के तहत प्रतिबंधित है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि धार्मिक स्थल के नाम पर की गई अवैध संरचनाएं कानून का उल्लंघन हैं और इन्हें हटाना अनिवार्य है।

गौरतलब है कि पिछले वर्ष जून-जुलाई में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वन विभाग ने अरावली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया था। करीब डेढ़ महीने तक चली कार्रवाई में लक्कड़पुर, अनंगपुर, अनखीर और मेवला महाराजपुर क्षेत्रों में 261 एकड़ से अधिक भूमि पर फैले 241 अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए थे। इस दौरान कुछ स्थानों पर विभाग को विरोध का सामना भी करना पड़ा था। बाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) का गठन कर स्थिति का आकलन कराया गया।

इधर, हाल में जारी एक अध्ययन रिपोर्ट में भी अरावली क्षेत्र में बढ़ते अतिक्रमण, अवैध खनन और शहरी विस्तार पर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, इन गतिविधियों से भूजल पुनर्भरण, जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अरावली पर्वतमाला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए प्राकृतिक अवरोध और पारिस्थितिक सुरक्षा कवच का काम करती है, ऐसे में इसके संरक्षण के लिए सख्त कदम उठाना आवश्यक है।

बजट के बाद पीएम मोदी का संबोधन, विकास को मज़बूत करने पर फोकस

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज बजट वेबिनार श्रृंखला के द्वितीय सत्र को संबोधित किया जिसका मुख्य विषय 'आर्थिक विकास बरकरार रखना और मजबूत करना' था। प्रधानमंत्री ने पिछले सप्ताह की प्रगति पर विचार करते हुए कहा कि पहला वेबिनार अत्यंत सफल रहा और बजट प्रावधानों के कार्यान्वयन के संबंध में उत्कृष्ट सुझाव प्राप्त हुए। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि वर्तमान वेबिनार देश की आर्थिक वृद्धि को निरंतर मजबूती प्रदान करने के मुद्दे से सहज रूप से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के पुनर्गठन के साथ भारत की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था विश्व के लिए आशा की किरण बन गई है। श्री मोदी ने कहा, 'अर्थव्यवस्था की तीव्र प्रगति 'विकसित भारत' की मजबूत नींव है।'

दिल्ली पुलिसः ऑपरेशन मिलाप के तहत 118 लापता व्यक्तियों और बच्चों को उनके परिवारों से मिलाया

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस के दक्षिण-पश्चिम जिला ने ऑपरेशन मिलाप के तहत पिछले महीने कुल एक सौ क्त लापता व्यक्तियों और बच्चों को उनके परिवारों से मिलाया है। जिनमें फ्क लापता और अपहृत बच्चे तथा त्स्त्र वयस्क शामिल हैं।

इसी कड़ी में इस वर्ष पहली जनवरी से ख्त फरवरी तक कुल एक सौ -फ लापता व्यक्तिओं और बच्चों को सुरक्षित उनके परिवारों से मिलाया है।

पुलिस ने स्थानीय पूछताछ, सीसीटीवी फुटेज समीक्षा, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर तस्वीर दिखाकर इन लापता लोगों और बच्चों को ढूंढा।

इसके अलावा, पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप के तहत किए गए प्रयासों की सराहना की है और आगे भी ऐसे प्रयास जारी रखने का आश्वासन दिया है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कनॉट प्लेस में एनडीएमसी फूल महोत्सव का उद्घाटन किया

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी के कनॉट प्लेस में एनडीएमसी फूल महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महोत्सव रंगों, प्रकृति और रचनात्मकता का एक जीवंत उत्सव है। उन्होंने कहा कि ट्रे गार्डन, पिरामिड और सिलेंडर के आकार में फूलों की सजावट, सुंदर परिदृश्य और विशेष सेल्फी पॉइंट इस आयोजन को और भी आकर्षक बना रहे हैं।

’وزیراعظم واضح کریں، کیا وہ سربراہِ مملکت کے قتل کی حمایت کرتے ہیں؟‘ راہل گاندھی کا مودی سے سوال

نئی دہلی: مشرقِ وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف اور کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی نے وزیراعظم نریندر مودی سے دوٹوک سوال کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ واضح کریں آیا وہ کسی سربراہِ مملکت کے قتل کو عالمی نظام کی تشکیل کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اپنے ایکس بیان میں راہل گاندھی نے امریکہ-اسرائیل اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی دشمنی پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ صورتحال ایک نازک خطے کو وسیع تنازعہ کی طرف دھکیل رہی ہے، جہاں کروڑوں افراد بشمول تقریباً ایک کروڑ ہندوستانی غیر یقینی حالات سے دوچار ہیں۔ راہل گاندھی نے کہا کہ سکیورٹی خدشات اپنی جگہ لیکن ایسی کارروائیاں جو کسی ملک کی خود مختاری کی خلاف ورزی کریں، بحران کو مزید گہرا کرتی ہیں۔ انہوں نے ایران پر یکطرفہ حملوں اور ایران کی جانب سے دیگر مغربی ایشیائی ممالک پر حملوں دونوں کی مذمت کی اور کہا کہ تشدد کا جواب مکالمہ اور تحمل کے ذریعے ہی دیا جا سکتا ہے۔ ان کے مطابق ایسے حساس وقت میں خاموشی ہندوستان کے عالمی وقار کو متاثر کرتی ہے اور خارجہ پالیسی کو اصولی بنیادوں پر استوار رہنا چاہیے۔ راہل گاندھی نے اپنی پوسٹ میں لکھا، ’’بین الاقوامی قانون اور انسانی جانوں کے دفاع میں ہمیں صاف اور دوٹوک انداز میں بات کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ ہماری خارجہ پالیسی خودمختاری اور تنازعات کے پرامن حل پر مبنی ہے اور اسے اسی تسلسل کے ساتھ برقرار رہنا چاہیے۔ وزیراعظم مودی کو بولنا چاہیے۔ کیا وہ عالمی نظام کی تشکیل کے ایک طریقے کے طور پر کسی سربراہِ مملکت کے قتل کی حمایت کرتے ہیں؟ اس وقت کی خاموشی ہندوستان کے عالمی وقار کو کمزور کرتی ہے۔‘‘ قبل ازیں سونیا گاندھی نے اپنے مضمون میں بھی اسی نوعیت کے خدشات ظاہر کیے تھے۔ انہوں نے لکھا کہ کسی خودمختار ریاست کی قیادت کو نشانہ بنانا عالمی قانون اور اقوام متحدہ کے اصولوں کے منافی ہے۔ ان کے مطابق ہندوستان کو اخلاقی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انسانی جانوں اور بین الاقوامی ضابطوں کے دفاع میں واضح مؤقف اختیار کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی خارجہ پالیسی ہمیشہ خودمختاری کے احترام اور تنازعات کے پرامن حل پر مبنی رہی ہے۔ سونیا گاندھی نے مزید کہا کہ عالمی نظام طاقت کے استعمال سے نہیں بلکہ قوانین کی پاسداری اور سفارتی تدبر سے مستحکم ہوتا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر بڑی طاقتیں یکطرفہ کارروائیوں کو معمول بنا لیں تو اس سے عالمی استحکام کمزور ہوگا اور ترقی پذیر ممالک سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ دوسری جانب کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے دو روز قبل اپنے بیان میں ایران کے سپریم لیڈر سید علی حسینی خامنہ ای کو ہدف بنا کر کی گئی کارروائی کی سخت الفاظ میں مذمت کی تھی۔ انہوں نے اسے بغیر اعلانِ جنگ کی گئی کارروائی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی ہے اور خود مختار ریاستوں کے داخلی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہے۔ کھڑگے نے کہا کہ آئینِ ہند کے آرٹیکل اکاون کے مطابق ہندوستان کی خارجہ پالیسی پرامن بقائے باہمی، عدم مداخلت اور عالمی قانون کے احترام پر مبنی ہے۔ ان کے مطابق کسی بھی ملک کی قیادت کو بیرونی طاقت کے ذریعے ہٹانے کی کوشش ایک خطرناک رجحان ہے جو منصفانہ عالمی نظام کے تصور سے متصادم ہے۔

منا ایکسپریس وے پر دردناک حادثہ میاں بیوی سمیت 6 کی موت

ہاتھرس: اتر پردیش کے ہاتھرس میں یمنا ایکسپریس وے پر منگل کو عالی الصبح ایک ڈبل ڈیکر بس نے چلتی ایکو وین کو پیچھے سے ٹکر ماردی جس کے نتیجے میں ایک بڑا حادثہ ہوگیا۔ اس حادثے میں میاں بیوی سمیت 6 لوگوں کی موت ہوگئی اور 7 دیگر زخمی ہوگئے۔ متوفیوں میں سے 3 آگرہ اور 3 راجستھان کے دھول پور کے رہنے والے تھے۔ یہ سبھی لوگ ہولی کے لیے گھر جارہے تھے۔ اطلاع کے مطابق حادثے کا شکار بس دہلی سے گورکھپور جارہی تھی جبکہ وین دہلی سے دھولپور جارہی تھی۔ اوورٹیک کی کوشش کے دوران ٹکر ہوئی۔ ٹکر اتنی بھیانک تھی کہ وین اُچھل کر 10 فٹ دور گری اور اس کا پچھلا حصہ چکنا چور ہوگیا۔ اس حادثے میں بس میں سوار مسافر پوری طرح محفوظ رہے۔ حادثے کے بعد موقع پر کہرام مچ گیا۔ ہر طرف سے چیخ وپکار مچ گئی۔ سڑک پر لاشیں بچھ گئیں جس کی وجہ سے ایکسپریس وے پر جام لگ گیا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اہلکار موقع پر پہنچ گئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر کھنڈولی سی ایچ سی بھیجا گیا، جہاں سے 3 کو آگرہ ریفر کردیا گیا۔ حادثہ سعد آباد کوتوالی علاقہ میں پیش آیا۔ ہاتھرس میں یمنا ایکسپریس وے کے مائل اسٹون 141 پر پرائیویٹ ڈبل ڈیکر بس گورکھپور کی طرف جارہی تھی۔ وہیں ایکو وین بس کے آگے چل رہی تھی۔ وین میں 13 افراد سوار تھے۔ سبھی لوگ ہولی کا تہوار منانے اپنے اپنے گھر جارہے تھے۔ اطلاعات کے مطابق علی الصبح 4 بج کر 15 منٹ پر تیز رفتار بس نے وین کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کی اور بے قابو ہوکر وین کو پیچھے سے ٹکر ماردی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ وین قریب 10 فٹ دور جا کر گری۔ جس کے نتیجے میں 6 لوگوں کی موت ہوگئی اور متعدد زخمی ہوگئے۔ زخمیوں میں 4 بچے بھی شامل ہیں۔ حادثہ میں زخمی ایکو ڈرائیور کی حالت نازک بتائی جارہی ہے۔ متوفیوں کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ اسپتال بھیج دیا گیا ہے۔

کیرالہ اور تمل ناڈو میں حد بندی کو مسئلہ بنائے گی کانگریس، جے رام رمیش نے بی جے پی کے ارادوں پر اٹھائے سوال

کیرالہ اور تمل ناڈو میں جلد ہی انتخابات ہونے والے ہیں۔ دونوں ریاستوں میں سیاسی سرگرمیاں تیز ہوگئی ہیں۔ اس دوران کانگریس لیڈر جے رام رمیش نے بحث کے لیے حد بندی کا مسئلہ اٹھاتے ہوئے بی جے پی کو نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے دلیل دی کہ جنوبی ریاستیں، جو اپنی آبادی کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرتی ہیں، کو کم پارلیمانی نشستوں کے ساتھ سزا نہیں دی جانا چاہیے۔ ’پی ٹی آئی‘ کو دیئے انٹرویو میں جے رام رمیش نے مرکزی فنڈز کی تقسیم میں امتیازی سلوک کا بھی الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ نمائندگی اور مالی انصاف دونوں ہی کیرالہ اور تمل ناڈو کے آئندہ انتخابات میں بی جے پی کو گھیرنے کے لیے اٹھائے جانے اہم مسائل ہوں گے۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا کیرالہ اور تمل ناڈو میں حد بندی انتخابی مہم کا مسئلہ بننے جارہی ہے، جے رام رمیش نے کہا کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ موجودہ صورتحال کے مطابق کیرالہ، کرناٹک، تمل ناڈو، تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں سیٹوں کی تعداد میں کمی آئے گی۔ یہ تشویش کی بات ہے۔ ابھی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ابھی مردم شماری ہونا باقی ہے۔ اگلے سال اپریل تک ہمیں مردم شماری کے نتائج معلوم ہوں گے۔ پھر یقینی طور پر ایک حد بندی کمیشن تشکیل دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ریاستیں، خاص طور پر جنوبی ہند کی ریاستوں کو خاندانی منصوبہ بندی کے پروگراموں کے معاملے میں اتنا ذمہ دار اور جوابدہ ہونے کی سزا دی جائے۔ کانگریس لیڈر نے کہا کہ کیرالہ ہندوستان کی پہلی ریاست ہے جس نے شرح پیدائش کو 1.2 تک کم کرنے کا ہدف حاصل کیا ہے۔ ان کی پالیسی کا مقصد شرح پیدائش کو 1.2 تک کم کرنا تھا۔ اس سطح پر آبادی دونسلوں کے بعد مستحکم ہونے لگے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تقریباً 40 سال پہلے کی بات ہے۔ کیرالہ 1988 میں 1.2 کی کل شرح پیدائش (ٹی ایف آر) تک پہنچ گئی۔

دبئی ایئرپورٹ بند، ہندوستانی مسافروں کی پریشان کن واپسی

ممبئی: ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملے اور ایران کی جوابی کارروائی کے بعد مشرق وسطیٰ کے حالات بدستور کشیدہ ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ کوئی یہ کہنے کی حالت میں نہیں ہے کہ ایک منٹ بعد کیا ہونے والا ہے۔ اس صورتحال نے دبئی سمیت دنیا کے کئی ممالک کے مسافروں کو بُری طرح متاثر کیا ہے۔ حملے اور جوابی حملے کے بعد کئی ممالک نے اپنی فضائی حدود بند کردی ہیں۔ وہیں دبئی ایئرپورٹ بھی بند کرکے پروازوں کو منسوخ کردیا گیا ہے۔ اس دوران دبئی گھومنے گئے کئی مسافر وہاں پھنس گئے تھے۔ اسی اثنا میں دبئی سے ایک پرواز منگل (3 مارچ) کی صبح تقریباً 2 بجے ممبئی کے چھترپتی شیواجی مہاراج بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اُتری۔ یہاں ایک وقت بڑی افراتفری کا ماحول نظر آیا۔ اس دوران پرواز کے ایک مسافر نے اپنی آنکھوں دیکھی صورت حال بیان کی۔ ’اے بی پی نیوز‘ کے مطابق ممبئی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ایک مسافر اجے نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم ممبئی سے حیدرآباد اور پھر وہاں سے دبئی پہنچے تھے۔ دبئی سے ہماری اگلی فلائٹ امریکہ کے لیے تھی۔ ہم فلائٹ میں سوار ہوگئے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جب فلائٹ ٹیک آف نہیں ہوئی تو پتہ کیا گیا۔ پہلے کوئی تکنیکی خرابی بتائی گئی۔ اسی طرح 8-7 گھنٹے گزر گئے۔ اس کے بعد ہم لوگوں کو بتایا گیا کہ خلیج میں جنگ شروع ہوگئی ہے، اس لئے ابھی ہم پرواز کرنے کی حالت میں نہیں ہیں۔ اجے نے بتایا کہ اس کے بعد ہوائی اڈے پر بھگدڑ مچ گئی۔ حالات انتہائی خراب ہو چکے تھے۔ پھر ایمریٹس کی بسیں اور گاڑیاں ایئرپورٹ پر پہنچیں اور ہمیں لے کر ہوٹلوں تک چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ہم لوگ ساری رات ہوٹل کے لیے بھٹکتے رہے۔ انہوں نے بتایا کہ 12-10 گھنٹے بھٹکنے کے بعد بالآخر ہم لوگوں کو ایک ہوٹل مل گیا۔ اس دوران ہم لوگوں نے بم کی آواز بھی سنی اور برج خلیفہ کے اردگرد دھوئیں کے غبار بھی دیکھے۔ وہیں ہمیں ہوٹل سے باہر نکلنے یا کھڑکیوں کے پاس کھڑے ہونے سے سختی سے منع کیا گیا۔ اجے نے بتایا کہ ہم دوپہر کا کھانا کھائے بغیر اپنے کمروں میں ہی بند رہے۔ ہم اس بات سے بے خبر تھے کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہاں ہر طرف افراتفری مچی ہوئی تھی۔ عوام بری طرح پریشان تھے۔

ہندوستان کی خارجہ پالیسی کو قومی مفاد پر پورا اترنا چاہیے، بی جے پی کی نظریاتی وابستگی سے نہیں: ایس ڈی پی آئی

نئی دہلی (پریس ریلیز) سوشیل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا (SDPI) کے قومی صدر ایم کے فیضی نے وزیراعظم نریندر مودی کے جاری اسرائیل کے دورے پر سخت تنقید کی ہے جبکہ مقبوضہ فلسطینی علاقہ بے مثال تباہی کو جھیل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دورہ مغربی ایشیا میں انصاف، متوازن سفارت کاری اور اسٹریٹجک خودمختاری کے تئیں ہندوستان کی تاریخی وابستگی سے ایک اہم تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ دفاعی تعاون اور تزویراتی ہم آہنگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب کہ غزہ کو بے پناہ انسانی مصائب کا سامنا ہے، حکومت کو ہندوستان کے دیرینہ آزاد خارجہ پالیسی کے فریم ورک سے سمجھوتہ کرنے کا خطرہ ہے۔ کئی دہائیوں تک ہندوستان فلسطینی عوام کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے۔ 1947 میں ہندوستان نے فلسطین کی تقسیم کے خلاف ووٹ دیا۔ 1974 میں، یہ پہلا غیر عرب ملک بن گیا جس نے فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کو فلسطینی عوام کا واحد جائز نمائندہ تسلیم کیا، اور 1988 میں اس نے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کیا۔ اس اصولی موقف کی بنیاد نوآبادیاتی مخالف یکجہتی اور خود ارادیت پر قائم تھی۔ تاہم، آج غزہ نے بڑے پیمانے پر شہری ہلاکتوں کا مشاہدہ کیا ہے، جن میں ہزاروں خواتین اور بچے شامل ہیں، گھروں کی تباہی، ہسپتالوں اور طبی سہولیات کو بار بار نقصان پہنچانا، اور ڈاکٹروں اور انسانی ہمدردی کے کارکنوں کا قتل ہو رہا ہے۔ بین الاقوامی ایجنسیوں نے بڑے پیمانے پر نقل مکانی، بھوک اور ضروری خدمات کے خاتمے کی رپورٹ کی ہے۔ ایسے نازک موڑ پر، اسرائیل کے ساتھ گہرے فوجی اور اسٹریٹجک تعلقات ایک گہرے پریشان کن سگنل بھیجتے ہیں۔ وزیراعظم نے پہلے مواقع پر اسرائیل کو ہندوستان کا قریبی دوست اور مضبوط اتحادی قرار دیا ہے اور موجودہ دورہ عوامی صف بندی کو مزید تقویت دیتا ہے۔ ہندوستان اور اسرائیل کے درمیان دوطرفہ دفاعی تجارت اربوں ڈالر میں چلتی ہے، ہندوستان اسرائیل کے فوجی ساز وسامان بشمول میزائل سسٹم، نگرانی کی ٹیکنالوجی اور بغیر پائلٹ کے فضائی گاڑیوں کے سب سے بڑے خریداروں میں سے ایک ہے۔ یہ بڑھتی ہوئی شراکت داری، جو تیزی سے نظر آتی ہے اور سیاسی طور پر منائی جاتی ہے، پہلے کے پالیسیوں سے منحرف ہونے کی نمائندگی کرتی ہے۔ پارٹی نے اس بات پر زور دیا کہ ہندوستان کے مفادات پورے مغربی ایشیا میں متوازن اور تعمیری تعلقات کی ضرورت ہے۔ لاکھوں ہندوستانی خلیجی ممالک میں رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں، اور ہندوستان کی توانائی کی سلامتی کا خطے سے گہرا تعلق ہے۔ کوئی بھی تاثر کہ بھارت گہرے پولرائزڈ علاقائی تنازعات میں فیصلہ کن طور پر ایک طرف جھک رہا ہے اس کے سفارتی اور اقتصادی نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ ایران کے ساتھ بڑھتے ہوئے علاقائی کشیدگی نے ہوشیاری کی ضرورت کو مزید واضح کیا ہے، خاص طور پر ہندوستان کی اسٹریٹجک سرمایہ کاری جیسے کہ چابہار بندرگاہ اور ہندوستان کو افغانستان اور وسطی ایشیا سے جوڑنے والے رابطے کے اقدامات کے پیش نظر حکمت کی ضرورت ہے۔ سوشیل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ نظریاتی وابستگی کے بجائے قومی مفاد میں جڑی متوازن خارجہ پالیسی کے لیے اپنی وابستگی کا اعادہ کرے۔ ہندوستان کو غزہ میں فوری جنگ بندی، شہریوں کے تحفظ، بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیوں کے لیے جوابدہی، اور مشرقی یروشلم کو ایک خودمختار فلسطین کے دارالحکومت کے طور پر دو ریاستی حل کے حقیقی احیاء کی وکالت جاری رکھنی چاہیے۔ ہندوستان کی خارجہ پالیسی کو اپنے عوام کے ضمیر، سلامتی اور طویل مدتی مفادات کی عکاسی کرنی چاہیے۔ اسے متعصّبانہ نظریہ یا علامتی صف بندیوں سے تشکیل نہیں دیا جا سکتا۔